

## वाणिज्य बैंकों के कार्य और निष्पादन

2011-12 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का निष्पादन देशी अर्थव्यवस्था में आयी नरमी से प्रभावित था जिससे बैंकों के तुलनपत्रों का विस्तार पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ। इसके अलावा, लाभप्रदता के प्रमुख संकेतक, अर्थात् आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ में कुछ गिरावट आयी। किंतु बैंकों के लागत-आय अनुपात में 2011-12 में सुधार हुआ जो उनकी कार्यकुशलता में सुधार दर्शाता है। पूंजी की दृष्टि से भारतीय बैंकों के सुदृढ़ रहने के बावजूद उनकी बढ़ती अनर्जक आस्तियों की चिंता में वृद्धि हुई। विशेष रूप से तनावग्रस्त बिजली और हवाई क्षेत्र के प्रति बैंकों के एक्सपोजर से उनकी आस्ति गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर हुआ। कवरेज का दायरा बढ़ाने में सुधार होने के बावजूद सार्थक वित्तीय समावेशन की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके साथ ही बैंकों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए ग्राहक सेवा को मजबूत करें।

### 1. भूमिका

4.1 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, जिसने 2008-09 के दौरान वैश्विक वित्तीय संकट की उथल-पुथल का सामना किया, में उसके बाद तनाव के कुछ चिह्न दिखने लगे। संकटोत्तर काल के दौरान भारतीय बैंकों का निष्पादन वैश्विक वित्तीय बाजारों में दुर्बल वृद्धि और देश के चुनौतीपूर्ण परिचालनात्मक वातावरण से प्रभावित था जिसमें मुद्रास्फीति अधिक थी और वृद्धि-निष्पादन मंद था। इसके अलावा, कुछ राज्यों के बिजली बोर्डों और हवाई कंपनियों की तनावपूर्ण वित्तीय स्थिति से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में और गिरावट आयी।

4.2 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) के 2011-12 के कार्य और निष्पादन का विश्लेषण किया गया है जो कि बैंकों के लेखापरीक्षित तुलनपत्रों और रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई परोक्ष विवरणियों पर आधारित है। इस अध्याय के विभिन्न खंडों में तुलनपत्रीय परिचालनों, लाभप्रदता और कार्यकुशलता के संकेतकों सुदृढ़ता की स्थिति, सीमापारीय परिचालन, पूंजी बाजार के परिचालन, ग्राहक सेवा और प्रौद्योगिकीय गतिविधियों पर फोकस किया गया है। वित्तीय समावेशन के तहत की योजनाओं में हुई प्रगति पर अलग खंड में चर्चा की गयी है। समापन खंड में इस विश्लेषण से उभरने वाले प्रमुख मुद्दों को रेखांकित किया गया है।

### 2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रीय परिचालन

**समेकित तुलनपत्रों का विस्तार कम हुआ जिसके मुख्य कारण जमाराशियों और साथ ही ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि मंद रहना थे**

4.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में मंद वृद्धि दर्ज हुई। देयता पक्ष में, वृद्धि में कमी का आधार व्यापक था अर्थात् पूंजी, जमाराशि और उधार की वृद्धि मंद थी। आस्ति पक्ष में, मंदी का मुख्य कारण ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि धीमी होना था जो देशी समष्टि-आर्थिक सभी प्रमुख घटकों में मंदी रहना दर्शाता है (सारणी IV.1 और IV.2)।

4.4 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलनपत्रों में गिरावट दर्शाते हुए बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों में उनका हिस्सा 2011-12 के दौरान कुछ कम हो गया। इसके बावजूद, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र कुल मिलाकर सार्वजनिक स्वरूप का बना रहा जिसमें मार्च 2012 के अंत में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा दो-तिहाई से अधिक था (चार्ट IV.1)।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का समेकित तुलनपत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च 2012 के अंत में							
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	एसबीआई समूह	राष्ट्रीयकृत बैंक*	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पूंजी	183	12	171	48	13	35	406	637
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	3,373	1,061	2,312	1,545	266	1,279	531	5,449
3. जमाराशियां	50,020	14,050	35,970	11,746	3,159	8,587	2,771	64,537
3.1. मांग जमाराशि	3,844	1,197	2,647	1,659	258	1,401	801	6,303
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	12,140	4,537	7,604	2,729	578	2,152	419	15,289
3.3. सावधि जमाराशि	34,036	8,317	25,719	7,358	2,323	5,035	1,551	42,945
4. उधार	4,618	1,588	3,030	2,584	198	2,386	1,199	8,401
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	2,186	1,002	1,184	855	114	741	929	3,970
<b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>	<b>60,380</b>	<b>17,712</b>	<b>42,668</b>	<b>16,778</b>	<b>3,750</b>	<b>13,028</b>	<b>5,836</b>	<b>82,994</b>
1. आरबीआई के पास नकदी और शेष	2,800	791	2,009	706	167	538	232	3,737
2. बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	1,760	482	1,278	366	71	295	312	2,437
3. निवेश	15,041	4,173	10,868	5,260	1,093	4,166	2,005	22,305
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां (क + ख)	12,580	3,513	9,067	3,474	785	2,688	1,376	17,429
a) भारत में	12,494	3,494	9,000	3,468	785	2,683	1,376	17,338
b) भारत के बाहर	85	19	67	5.6	-	5.6	-	91
3.2 अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों	10	0.2	9.7	0.2	0.2	0.01	-	10
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां	2,451	660	1,791	1,786	308	1,478	629	4,866
4. ऋण और अग्रिम	38,783	11,520	27,263	9,664	2,301	7,363	2,298	50,746
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	2,307	888	1,419	357	113	244	257	2,922
4.2 कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, आदि	16,085	4,958	11,127	2,860	1,120	1,740	1,099	20,044
4.3 सावधि ऋण	20,391	5,674	14,717	6,447	1,068	5,380	942	27,780
5. अचल आस्तियां	383	74	309	134	27	107	50	567
6. अन्य आस्तियां	1,613	672	941	649	91	558	939	3,201

टिप्पणी: - कुछ नहीं/ नगण्य। आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण घटकों और उनके योग में अंतर हो सकता है।

\*: आईडीबीआई बैंक लि. सहित।

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रमुख देयताएं

जमाराशि में मंद वृद्धि दर्ज हुई

4.5 मार्च 2012 के अंत में, बैंकिंग क्षेत्र की कुल देयताओं के तीन-चौथाई से अधिक भाग जमाराशि का था। जमाराशि पिछले वर्ष की तुलना में कम गति से बढ़ी जिसका मुख्य कारण मांग जमाराशि में संकुचन और बचत बैंक जमाराशि की मंद वृद्धि था। दूसरी ओर, सावधि जमाराशियों की वृद्धि बढ़ गयी। इसके अलावा, मांग और बचत बैंक जमाराशि, जो कि निधि के न्यूनतम लागत के स्रोत हैं, के संग्रह में नरमी से भारतीय बैंकों की लाभप्रदता कम होने का दबाव बन सकता है (सारणी IV.2)।

कुल जमाराशि में चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों का अनुपात कम हुआ

4.6 2011-12 के दौरान कुल जमाराशि में चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों का हिस्सा कम हो गया जिसका कारण मांग जमाराशि में गिरावट आना और बचत बैंक जमाराशि संग्रह में कमी आना था। मार्च 2012 के अंत में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशि का लगभग एक-तिहाई हिस्सा चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों का था। जमाराशि की संरचना के बैंक समूह-वार विश्लेषण से पता चलता है कि चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों का अधिकतम अनुपात विदेशी बैंकों का था जिनके बाद निजी क्षेत्र के नए बैंकों का स्थान था। इसे इस तथ्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्टूबर

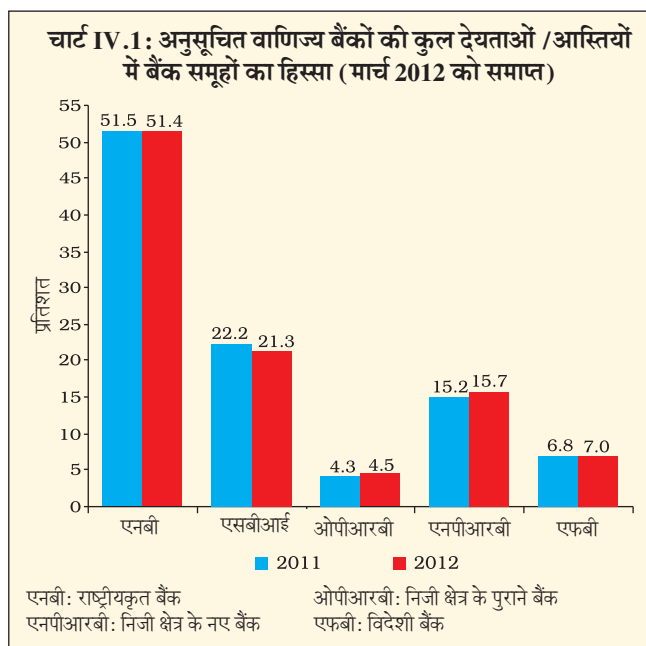
**सारणी IV.2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि**

(प्रतिशत)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी	40.7	-4.2	5.1	-	7.9	-4.2	4.1	1.7	15.1	15.6	21.3	8.0
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	19.3	24.4	15.9	15.5	18.7	18.5	15.4	14.9	18.8	15.7	18.2	20.8
3. जमाराशियां	18.4	14.4	21.9	17.1	14.9	19.6	24.6	16.3	3.7	15.1	18.3	14.9
3.1. मांग जमाराशियां	11.3	-6.3	18.1	4.4	12.2	6.5	19.2	4.0	6.8	9.9	12.3	-1.8
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	22.1	12.1	23.0	19.1	14.0	16.3	25.8	19.9	8.8	5.6	21.8	13.1
3.3. सावधि जमाराशियां	18.2	18.2	22.5	19.7	15.5	22.1	25.8	18.6	0.6	21.0	18.2	18.6
4. उधार	26.4	16.4	24.5	38.9	26.4	80.3	24.4	36.4	36.1	29.1	27.1	24.4
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	20.9	-6.8	21.0	20.6	-0.7	13.5	25.6	21.8	16.3	21.3	20.0	3.9
<b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>	<b>19.2</b>	<b>14.1</b>	<b>21.5</b>	<b>20.0</b>	<b>14.9</b>	<b>21.4</b>	<b>23.5</b>	<b>19.6</b>	<b>12.8</b>	<b>18.8</b>	<b>19.2</b>	<b>15.5</b>
1. आरबीआई के पास नकदी और शेष	30.1	-20.5	13.5	-18.1	7.4	-7.9	15.2	-20.8	6.3	14.2	25.4	-18.5
2. बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	9.3	40.7	-18.2	15.6	-31.3	80.4	-16.0	6.5	33.2	13.8	6.0	32.4
3. निवेश	9.9	12.6	19.2	24.6	11.0	18.0	21.7	26.5	3.9	21.1	11.3	16.0
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां	7.4	16.2	9.1	32.0	6.3	21.5	10.1	35.4	-4.7	22.9	6.6	19.6
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-43.4	-65.1	-71.4	-78.8	-82.2	-65.0	74.8	-97.6	-57.1	-100.0	-45.1	-65.6
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां	23.9	-2.2	41.0	12.5	24.9	10.0	45.0	13.0	28.1	17.5	29.8	5.1
4. ऋण और अग्रिम	22.3	17.4	26.1	21.2	19.8	24.6	28.1	20.1	19.8	17.6	22.9	18.1
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	30.3	25.8	20.2	8.2	10.3	14.7	25.0	5.5	10.2	9.6	26.6	21.8
4.2 केश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, आदि	24.0	17.9	41.2	27.6	23.4	33.3	54.6	24.2	27.1	18.4	26.2	19.2
4.3 सावधि ऋण	20.3	16.1	21.1	19.3	17.8	17.7	21.8	19.6	14.9	18.9	20.3	16.9
5. अचल आस्तियां	4.9	5.9	26.8	3.0	6.5	6.9	32.8	2.1	2.0	1.2	9.1	4.8
6. अन्य आस्तियां	33.9	15.3	21.6	35.5	12.0	28.0	23.4	36.8	13.5	21.1	25.0	20.7

- : नगण्य/शून्य।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।



2011 में बचत बैंक ब्याज दर को अविनियमित करने के बाद निजी क्षेत्र के अनेक बैंकों ने अपनी बचत बैंक जमाराशि दरों में वृद्धि की थी (चार्ट IV.2)।

**2011-12 के दौरान उधार का सहारा अधिक लिया गया**

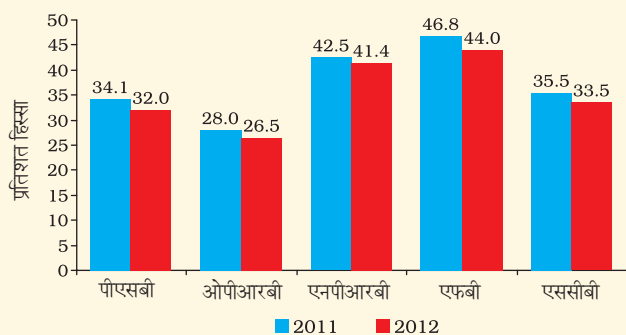
4.7 मार्च 2012 के अंत में, उधार बैंकिंग क्षेत्र की कुल देयताओं के लगभग 10 प्रतिशत थे जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक थे (सारणी IV.1)।

**अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रमुख आस्तियां**

**मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के कारण ऋण लेने में कमी रही**

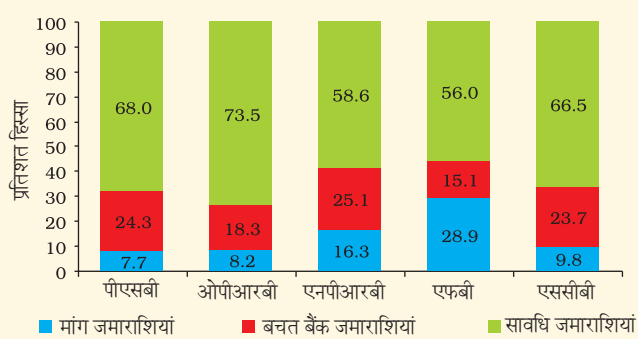
4.8 कुल ऋण और अग्रिम की वृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में कमी रही। 2011-12 के दौरान बैंक ऋण में गिरावट

**चार्ट IV.2क: कुल जमाराशियों में सीएएसए जमाराशियों का हिस्सा (मार्च को समाप्त)**



पीएसबी: सरकारी क्षेत्र के बैंक ओपीआरबी: निजी क्षेत्र के पुराने बैंक एनपीआरबी: निजी क्षेत्र के नए बैंक एफबी: विदेशी बैंक एससीबी: अनुसूचित वाणिज्य बैंक

**चार्ट IV.2ख: जमाराशियों की संरचना (मार्च 2012 को समाप्त)**



व्यापक आधार की थी जिसमें सभी प्रमुख क्षेत्रों द्वारा ऋण लेने में कमी आयी थी। उद्योग और सेवा क्षेत्र को ऋण, जो कि कुल बैंक ऋण में संयुक्त रूप से दो-तिहाई से अधिक था, में धीमी वृद्धि हुई।

### सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक निवेश से बैंकों द्वारा जोखिम से बचने की प्रवृत्ति दिख रही थी

4.9 बैंकों के तुलनपत्रों की मुख्य मदों में देखी गयी समग्र नरमी के विपरीत पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान निवेश वृद्धि बढ़ गयी। ऋण वृद्धि में गिरावट के विपरीत बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में काफी वृद्धि हुई। यह प्रवृत्ति आंशिक रूप से इस बात को दर्शाती है कि दुर्बल समष्टिआर्थिक संभावना और बढ़ती अनर्जक आस्तियों को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने जोखिम से बचते हुए अपनी निधि को अधिक सुरक्षित लिखत में रखना पसंद किया।

### एसएलआर से भिन्न लिखतों में निवेश में गिरावट

4.10 मार्च 2012 के अंत में, बैंकों द्वारा एसएलआर से भिन्न लिखत में निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आयी जिसका कारण शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश में कमी आना था। म्यूचुअल फंड में निवेश में कमी आने का आंशिक कारण म्यूचुअल फंड की अल्पकालिक ऋण योजनाओं/चलनिधि में बैंकों के एक्सपोजर को नियंत्रित करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक

द्वारा नीति को कड़ा करना हो सकता है। किंतु वाणिज्यिक पत्रों में बैंकों के निवेश में तेज वृद्धि हुई (सारणी IV.3)।

### सारणी IV.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ बिलियन में)

लिखत	23 मार्च 2012 की स्थिति	पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि की तुलना में वृद्धि	21 सितंबर 2012 की स्थिति	पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि की तुलना में वृद्धि
1	2	3	4	5
<b>1 वाणिज्यिक पत्र</b>	<b>196 (7.2)</b>	<b>59.2</b>	<b>357 (10.9)</b>	<b>90.6</b>
<b>2 शेयर</b>	<b>402 (14.8)</b>	<b>-12.0</b>	<b>426 (13.2)</b>	<b>-1.4</b>
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	72		76	
ख) जिसमें से, निजी कंपनी क्षेत्र	301		318	
ग) सरकारी वित्तीय संस्थाएं	23.8		25	
घ) अन्य	5.2		7	
<b>3 बांड / डिबेंचर</b>	<b>1,861 (68.7)</b>	<b>11.5</b>	<b>2,002 (61.2)</b>	<b>15.5</b>
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	412		341	
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	741		884	
ग) सरकारी वित्तीय संस्थाएं	359		342	
घ) अन्य	349		435	
<b>4 यूटीआई की इकाइयां/ अन्य म्यूचुअल फंड</b>	<b>251 (9.3)</b>	<b>-47.2</b>	<b>485 (14.8)</b>	<b>-26.8</b>
<b>कुल निवेश (1 से 4)</b>	<b>2,710 (100.0)</b>	<b>-0.6</b>	<b>3,270 (100.0)</b>	<b>8.4</b>

**टिप्पणी:** आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकता है।

**स्रोत:** अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत खंड 42 (2) की विवरणियां।

## अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

### कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में कम वृद्धि हुई, वहीं अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में उच्च वृद्धि दर्ज हुई

4.11 2010-11 में, बैंकों की कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं पिछले वर्ष की तुलना में कम दर पर बढ़ीं जिसका मुख्य कारण देशी बैंकों द्वारा जारी एडीआर/जीडीआर में कमी आने के कारण अन्य देयताओं में कमी आना था। किंतु, अनिवासी बाह्य रुपया जमाराशि के माध्यम से हुए अंतर्वाहों में वृद्धि हुई जिसका कारण अनिवासी बाह्य खातों के तहत की बचत जमाराशि और मीयादी जमाराशि - दोनों पर ब्याज दरों को अविनियमित करने के कारण

#### सारणी IV.4: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - प्रकारानुसार ( ₹ बिलियन)

देयताओं का प्रकार	बकाया राशि (मार्च अंत की स्थिति)		प्रतिशत में घटबढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
<b>1. जमा और उधार</b>	<b>3,782 (72.5)</b>	<b>4,472 (79.0)</b>	<b>11.7</b>	<b>18.2</b>
<i>जिसमें से:</i>				
क) विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक हफ्सीएनआर (बी) ज्योजना	774 (14.8)	805 (14.2)	7.2	4.0
ख) विदेशी मुद्रा उधार *	954 (18.3)	1,100 (19.4)	28.3	15.3
ग) अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) खाता	1,212 (23.2)	1,626 (28.7)	-0.9	34.1
घ) अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया जमा	411 (7.9)	532 (9.4)	33.2	29.6
<b>2. प्रतिभूति/बांड के अपने निर्गम</b>	<b>46 (0.9)</b>	<b>56 (1.0)</b>	<b>-15.9</b>	<b>23.0</b>
<b>3. अन्य देयताएं</b>	<b>1,387 (26.6)</b>	<b>1,133 (20.0)</b>	<b>28.2</b>	<b>-18.3</b>
<i>जिसमें से:</i>				
क) एडीआर / जीडीआर	347 (6.7)	271 (4.8)	14.2	-21.8
ख) अनिवासियों के पास बैंकों की इक्विटीज	732 (14.0)	536 (9.5)	45.4	-26.8
ग) भारत स्थित विदेशी बैंकों की पूंजी/प्रेषण योग्य लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताएं	308 (5.9)	326 (5.8)	12.2	5.8
<b>कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं</b>	<b>5,215 (100.0)</b>	<b>5,661 (100.0)</b>	<b>15.3</b>	<b>8.6</b>

\* भारत में और विदेश से अंतर-बैंक उधार, बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं।  
टिप्पणी: 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल देयताओं की तुलना में प्रतिशत हैं।  
2. एलबीएस (लोकेशनल बैंकिंग सांख्यिकीय) विवरणियों के आधार पर।  
3. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकता है।

अनिवासी बाह्य मीयादी जमाराशि के तहत की ब्याज दर में वृद्धि होना हो सकता है (सारणी IV.4)।

4.12 इसके विपरीत, बैंकिंग क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में उच्च वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण और नोस्ट्रो शेष थे (सारणी IV.5)।

### समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में उच्च वृद्धि हुई

4.13 पिछले वर्ष की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए 2011-12 में कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में उच्च वृद्धि हुई। किंतु कुल अंतरराष्ट्रीय दावों की अवधिपूर्णता (अवशिष्ट)-वार और क्षेत्र-वार संरचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ (सारणी IV.6)। भारत से भिन्न देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय

#### सारणी IV.5: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां - प्रकारानुसार ( ₹ बिलियन)

आस्तियों के प्रकार	बकाया राशि		प्रतिशत में घटबढ़	
	मार्च 2011	मार्च 2012	2010-11	2011-12
<b>1. ऋण और निवेश</b>	<b>2,787 (96.8)</b>	<b>3,410 (97.3)</b>	<b>17.5</b>	<b>22.3</b>
<i>जिसमें से:</i>				
क) अनिवासियों को उधार *	144 (5.0)	156 (4.4)	41.4	8.1
ख) निवासियों को विदेशी मुद्रा उधार **	1,401 (48.6)	1,652 (47.2)	13.4	17.9
ग) निवासियों द्वारा अनिवासियों पर जारी बकाया निर्यात बिल	613 (21.3)	725 (20.7)	21.4	18.3
घ) नोस्ट्रो शेष @	624 (21.7)	865 (24.7)	19.6	38.7
<b>2. ऋण प्रतिभूतियों की धारिताएं</b>	<b>2.0 (0.1)</b>	<b>- (0.0)</b>	<b>351.3</b>	<b>-</b>
<b>3. अन्य आस्तियां @@</b>	<b>91 (3.2)</b>	<b>94 (2.7)</b>	<b>0.1</b>	<b>2.9</b>
<b>कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियां</b>	<b>2,881 (100.0)</b>	<b>3,504 (100.0)</b>	<b>16.9</b>	<b>21.6</b>
* अनिवासियों की जमाराशियों में से रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण को शामिल किया गया है।				
** एफसीएनआर (बी) जमाराशियों में से दिए गए उधार और विदेशी मुद्रा में बैंकिंग ऋण (पीसीएफसी) तथा भारत स्थित बैंकों में जमा राशियां और एफसी उधार आदि।				
@ विदेश में किए गए प्लेसमेंट एवं अनिवासी बैंकों के पास शेष मीयादी जमाराशियां।				
@@ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक संस्थाओं को आपूर्ति की गई पूंजी और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय आस्तियां।				
<b>टिप्पणी:</b> 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल देयताओं की तुलना में प्रतिशत हैं; - शून्य/नगण्य।				
2. एलबीएस (लोकेशनल बैंकिंग सांख्यिकीय) विवरणियों के आधार पर।				
3. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकता है।				
4. - : शून्य/नगण्य।				

दावों में वृद्धि में यूएई, हांगकांग, अमरीका, सिंगापुर और यूके का योगदान प्रमुख था (सारणी IV.7)।

### ऋण-जमाराशि तथा निवेश-जमाराशि अनुपात

#### वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात निवेश-जमाराशि अनुपात की तुलना में काफी अधिक बना रहा

4.14 वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात 2011-12 की पहली तीन तिमाहियों में कम हो गया जो कि बैंक ऋण में नरमी दर्शाता

#### सारणी IV.6 : बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - परिपक्वता (अवशिष्ट) और क्षेत्रवार

( ₹ बिलियन )

अवशिष्ट परिपक्वता / क्षेत्र	बकाया राशि		प्रतिशत में घटबढ़	
	मार्च 2011	मार्च 2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
<b>कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे</b>	<b>2,464 (100.0)</b>	<b>2,809 (100.0)</b>	<b>5.9</b>	<b>14.0</b>
<b>क) परिपक्वता-वार</b>				
1. अल्पावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम)	1,539 (62.5)	1,832 (65.2)	6.6	19.0
2. दीर्घावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष और ऊपर)	872 (35.4)	924 (32.9)	6.5	5.9
3. अनाबंटित	53 (2.1)	54 (1.9)	-18.8	1.7
<b>ख) क्षेत्रवार</b>				
1. बैंक	1,091 (44.3)	1,286 (45.8)	11.5	17.8
2. गैर-बैंक सार्वजनिक	9 (0.4)	19 (0.7)	-39.7	114.1
3. गैर-बैंक निजी	1,364 (55.4)	1,505 (53.6)	2.2	10.3

#### टिप्पणियां:

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
- अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में परिपक्वता लागू नहीं (अर्थात इक्विटी के लिए) और बैंक शाखाओं से उपलब्ध न करायी गई परिपक्वता सूचना शामिल है।
- बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी मौद्रिक संस्थाएं (जैसे आईएफसी, ईसीबी आदि) और केंद्रीय बैंक शामिल हैं।
- मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से पूर्व, 'गैर-बैंक सार्वजनिक क्षेत्र' में बैंकों को छोड़कर ऐसी कंपनियां/संस्थाएं शामिल थीं जिनमें राज्य / केंद्र सरकार और उसके विभागों सहित राज्य/केंद्र सरकारों की कम-से-कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता थी। मार्च 2005 की तिमाही से 'गैर-बैंक सार्वजनिक' क्षेत्र में केवल राज्य/केंद्र सरकार और उनके विभाग शामिल हैं और तदनुसार, बैंकों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाएं 'गैर-बैंक निजी क्षेत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये हैं।
- समेकित बैंकिंग सांख्यिकी विवरणियाँ-निकटवर्ती देशगत जोखिम पर आधारित।
- आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

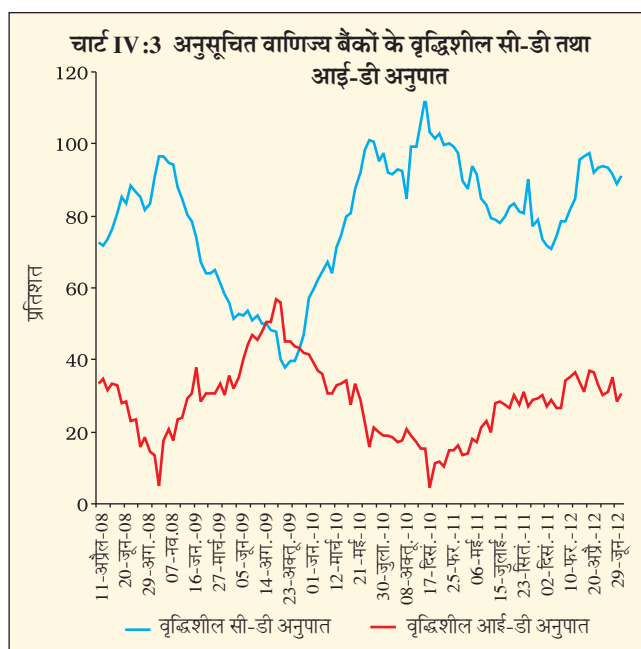
#### सारणी IV.7: भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

( ₹ बिलियन )

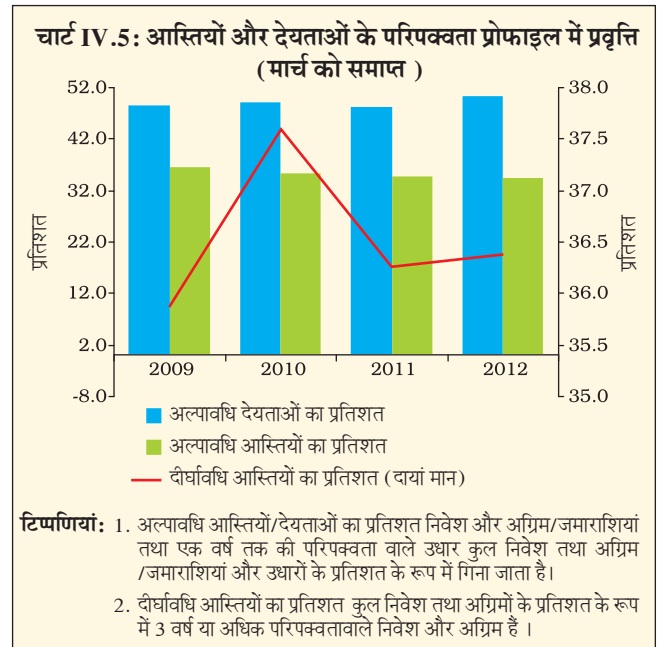
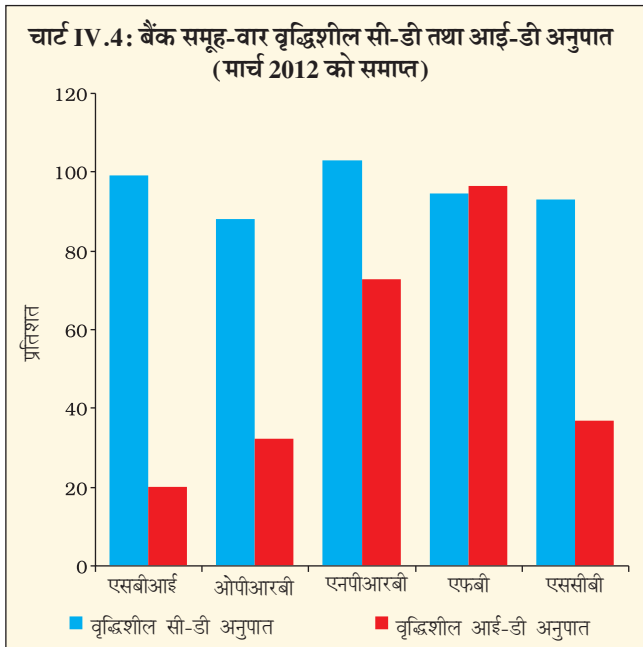
देश	बकाया राशि		प्रतिशत में घटबढ़	
	मार्च 2011	मार्च 2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
<b>कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे</b>	<b>2,464 (100.0)</b>	<b>2,809 (100.0)</b>	<b>5.9</b>	<b>14.0</b>
<i>जिसमें से:</i>				
1. अमरीका	548 (22.2)	643 (22.9)	3.2	17.2
2. यूनाइटेड किंगडम	344 (13.9)	364 (13.0)	-4.9	6.0
3. हांगकांग	184 (7.5)	220 (7.8)	-3.2	19.5
4. सिंगापुर	185 (7.5)	216 (7.7)	0.6	16.3
5. संयुक्त अरब अमीरात	155 (6.3)	221 (7.9)	14.5	42.8
6. जर्मनी	142 (5.7)	118 (4.2)	16.3	-16.6

- टिप्पणियां :**
- आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।
  - कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

है। वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात निजी क्षेत्र के नए बैंकों के संबंध में अधिक था जबकि विदेशी बैंकों में निवेश-जमाराशि अनुपात अधिक था (चार्ट IV.3 और चार्ट IV.4)<sup>1</sup>।



<sup>1</sup> बैंक समूहों के वृद्धिशील ऋण-जमाराशि और निवेश-जमाराशि अनुपात मार्च 2011 के अंत और मार्च 2012 के अंत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनापत्रों से परिकलित किए गए थे।



## आस्तियों और देयताओं का अवधिपूर्णाता प्रोफाइल

**अवधिपूर्णाता का असंतुलन निरंतर बना रहा जिसमें अल्पकालिक देयताओं का अनुपात बढ़ रहा था**

4.15 आस्तियों और देयताओं की औसत अवधिपूर्णाता प्रोफाइल में निरंतर असंतुलन बने रहना भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए हाल में चिंता का विषय रहा है। अल्पावधि देयता अनुपात 2008 से बढ़ा है। दूसरी ओर, कुल आस्तियों में अल्पकालिक आस्तियों का अनुपात 2008 से कम हो गया है (चार्ट IV.5 और सारणी IV.8)।

## अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रेतर परिचालन

**तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों में लगातार वृद्धि होती रही हालांकि इसकी गति धीमी थी**

4.16 हाल के वर्षों में, बैंकों के तुलनपत्रेतर कार्य रिजर्व बैंक की संवीक्षा के तहत आए हैं, विशेष रूप से इस कारण कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजर में अत्यधिक वृद्धि वैश्विक वित्तीय संकट के मुख्य कारणों में से एक रही है। 2011-12 के दौरान, बैंकों की कुल तुलनपत्रेतर देयताओं (आनुमानिक) में पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि हुई। तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के बैंक समूह-वार विश्लेषण से पता

चला कि तुलनपत्रीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (आनुमानिक) अन्य बैंक समूहों की तुलना में विदेशी बैंकों के संबंध में काफी अधिक था जिसका कारण वायदा संविदा, गारंटी और स्वीकृतियों/अनुसमर्थनों में उनका अधिक एक्सपोजर था (चार्ट IV.6 और परिशिष्ट सारणी IV.2)।

## 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय निष्पादन

4.17 बैंकों का वित्तीय निष्पादन 2011-12 के दौरान दबाव में आ गया जिसका मुख्य कारण ब्याज दरों में वृद्धि के वातावरण की पृष्ठभूमि में जमाराशि की लागत में वृद्धि होना था। किंतु, सकारात्मक रूप से, बैंक की कार्यकुशलता में सुधार हुआ। लाभप्रदता के दो मुख्य संकेतक, अर्थात् इक्विटी पर प्रतिलाभ और आस्ति पर प्रतिलाभ में 2011-12 के दौरान कुछ गिरावट हुई जो बैंकों के निवल लाभ में गिरावट दर्शाता है।

## लाभप्रदता

**ब्याज व्यय बढ़ने के कारण समेकित निवल लाभ वृद्धि कम हो गई**

4.18 कुल आय वृद्धि बढ़ने के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र का समेकित निवल लाभ पिछले वर्ष की तुलना में कम दर पर बढ़ा जिसका मुख्य कारण ब्याज व्यय में तेज वृद्धि होना था।

**सारणी IV.8: चुनिदां देयताओं / आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल**  
(मार्च अंत की स्थिति)

(प्रत्येक मद के अंतर्गत कुल का प्रतिशत)

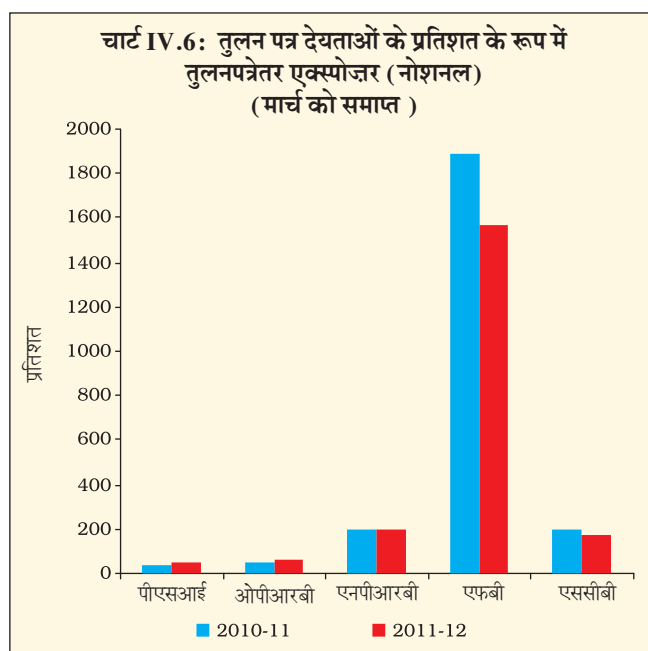
देयताएं / आस्तियाँ	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. जमाराशियाँ</b>												
क) 1 वर्ष तक	48.2	49.6	46.1	48.7	45.3	48.1	46.4	48.9	63.7	61.8	48.5	50.0
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	28.6	25.3	38.6	30.0	40.6	39.2	37.9	26.6	27.3	29.8	30.4	26.3
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	8.1	8.5	6.1	5.7	8.5	6.9	5.2	5.2	8.9	8.3	7.8	8.0
घ) 5 वर्ष से अधिक	15.1	16.6	9.1	15.7	5.6	5.8	10.4	19.3	-	0.1	13.4	15.7
<b>II. उधार राशियाँ</b>												
क) 1 वर्ष तक	39.9	45.4	42.4	50.3	54.5	63.7	41.7	49.2	78.8	84.5	46.1	52.6
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	12.5	12.2	16.2	11.8	12.5	13.4	16.4	11.7	14.7	9.2	13.8	11.7
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	12.3	15.2	9.8	12.5	11.4	7.8	9.7	12.9	2.1	2.7	10.2	12.5
घ) 5 वर्ष से अधिक	35.3	27.2	31.6	25.4	21.6	15.1	32.2	26.2	4.4	3.5	29.9	23.2
<b>III ऋण और अग्रिम</b>												
क) 1 वर्ष तक	36.0	34.3	37.6	35.2	41.9	44.0	36.3	32.4	68.1	67.4	37.8	35.9
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	36.3	37.4	36.4	37.1	38.4	36.1	35.8	37.4	17.0	15.5	35.4	36.3
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	10.9	11.0	11.4	11.3	9.9	9.1	11.9	12.0	4.2	4.5	10.7	10.8
घ) 5 वर्ष से अधिक	16.8	17.3	14.5	16.4	9.8	10.8	16.0	18.2	10.7	12.5	16.1	17.0
<b>IV. निवेश</b>												
क) 1 वर्ष तक	18.1	20.1	36.6	42.5	28.7	30.3	38.8	45.7	79.9	76.6	27.5	30.4
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	12.7	12.6	22.7	17.3	12.2	12.2	25.6	18.6	14.2	12.9	15.0	13.7
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	14.4	14.2	10.0	9.2	11.7	13.0	9.5	8.2	3.4	5.2	12.4	12.2
घ) 5 वर्ष से अधिक	54.8	53.1	30.7	31.0	47.3	44.4	26.1	27.5	2.5	5.3	45.0	43.7

टिप्पणी: कुछ नहीं/नगण्य

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।

4.19 जमाराशि पर व्यय हुआ ब्याज बैंकों के कुल ब्याज व्यय के तीन-चौथाई से अधिक था। इसके कारण और तुलनात्मक

रूप से अधिक लागत वाली जमाराशि के अनुपात में वृद्धि होने के कारण बैंकों की ब्याज लागत बढ़ गयी। इसके अलावा, उच्च ब्याज दर के वातावरण की पृष्ठभूमि में खुदरा जमाराशि की लागत अधिक बढ़ गयी।



**निवल ब्याज मार्जिन कुछ कम हो गयी**

4.20 2011-12 के दौरान, बैंकों का निवल ब्याज मार्जिन पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम हो गया जो मुख्यतः ब्याज व्यय में तेज वृद्धि दर्शाती है (सारणी IV.9)।

**निवल लाभ में कमी आने के कारण आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ कुछ कम हो गया**

4.21 2011-12 के दौरान, लाभप्रदता के दो प्रमुख संकेतक - आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम हो गया जो मुख्यतः यह दर्शाता है कि ब्याज व्यय में वृद्धि होने से निवल लाभ भी कम हो गया (सारणी IV.10)।



**सारणी IV.9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय की प्रवृत्ति**

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2010-11		2011-12	
	राशि	प्रतिशत घटबढ़	राशि	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5
<b>1. आय</b>	<b>5,712</b>	<b>15.5</b>	<b>7,408</b>	<b>29.7</b>
क) ब्याज आय	4,913	18.3	6,551	33.3
ख) अन्य आय	799	0.7	857	7.3
<b>2. व्यय</b>	<b>5,009</b>	<b>14.5</b>	<b>6,591</b>	<b>31.6</b>
क) व्यय किया गया ब्याज	2,989	9.9	4,305	44.0
ख) परिचालन व्यय	1,231	23.1	1,371	11.3
जिसमें से : वेतन बिल	727	31.6	780	7.3
ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	788	20.8	915	16.1
<b>3. परिचालन लाभ</b>	<b>1,491</b>	<b>22.0</b>	<b>1,732</b>	<b>16.1</b>
<b>4. निवल लाभ</b>	<b>703</b>	<b>23.2</b>	<b>817</b>	<b>16.1</b>
<b>5. निवल ब्याज आय (1क-2क)</b>	<b>1,924</b>	<b>34.5</b>	<b>2,245</b>	<b>16.7</b>
<i>ज्ञापन मद:</i>				
<b>निवल ब्याज मार्जिन (औसत आस्तियों के रूप में एनआईआई)</b>	<b>2.91</b>		<b>2.90</b>	

नोट: आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

बैंक समूह की आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ का अधिक विस्तृत विश्लेषण बॉक्स IV.1 में दिया गया है।

**कार्यकुशलता**

**आय अनुपात की लागत के अनुसार निर्धारित परिचालनात्मक कार्यकुशलता में सुधार हुआ**

4.22 2011-12 के दौरान, लागत-आय अनुपात<sup>2</sup> के संदर्भ में बैंकों की परिचालनात्मक कार्यकुशलता में सुधार हुआ। कार्यकुशलता के अन्य संकेतक, निवल आय मार्जिन में कुछ गिरावट आई अर्थात् वित्तीय मध्यस्थता लागत कम हो गई (चार्ट IV.7)।

**निधि पर प्रतिलाभ/लागत**

**निधि लागत वृद्धि के कारण बैंकों का स्प्रेड कम हो गया**

4.23 2011-12 के दौरान, बैंकों के लिए निधि की लागत और साथ ही उसपर प्रतिलाभ में वृद्धि हुई। किंतु निधि की लागत में अधिक वृद्धि होने के कारण स्प्रेड में कमी आ गयी। बैंक समूह

<sup>2</sup> कुल आय के प्रतिशत के रूप में परिचालन व्यय के रूप में गणना की गयी।

**सारणी IV.10: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल तथा इक्विटी पर प्रतिफल - बैंक समूह-वार**

(प्रतिशत)

बैंक समूह/वर्ष	आस्तियों पर प्रतिफल		इक्विटी पर प्रतिफल	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
<b>1 सरकारी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>0.96</b>	<b>0.88</b>	<b>16.90</b>	<b>15.33</b>
1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*	1.03	0.88	18.19	15.05
1.2 एसबीआई समूह	0.79	0.89	14.11	16.00
<b>2 निजी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>1.43</b>	<b>1.53</b>	<b>13.70</b>	<b>15.25</b>
2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.12	1.20	14.11	15.18
2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.51	1.63	13.62	15.27
<b>3 विदेशी बैंक</b>	<b>1.75</b>	<b>1.76</b>	<b>10.28</b>	<b>10.79</b>
<b>सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक</b>	<b>1.10</b>	<b>1.08</b>	<b>14.96</b>	<b>14.60</b>

**टिप्पणियाँ:** 1. समूह के लिए आस्तियों पर प्रतिलाभ समूह में एकल बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ के भारांकित औसत के रूप में लिया गया है, जो कि समूह की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल आस्तियों का अनुपात है।  
2. इक्विटी पर प्रतिफल = चालू और पिछले वर्ष के लिए पूंजी और आरक्षित निधि और अधिशेष का निवल लाभ / औसत।  
3. \* राष्ट्रीयकृत बैंकों में आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्तर पर, निधि की लागत विदेशी बैंकों के मामले में कम थी जिसका आंशिक कारण विदेशी बैंकों की कुल जमाराशि में चालू खाता और बचत खाता जमाराशि का अनुपात अधिक होना था (सारणी IV.11 और चार्ट IV.8)।

**4. सुदृढ़ता संकेतक**

4.24 भारत स्थित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक 1 अप्रैल 2009 से मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बासल II अनुपालक बन गए हैं। बासल II के उन्नत स्तर में अंतरण के लिए रिजर्व बैंक ने दिशानिर्देशों का अलग सेट जारी किया और बैंकों द्वारा बासल II के उन्नत स्तर में अंतरण के लिए किए गए आवेदन रिजर्व बैंक में जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं। इस प्रक्रिया के समानांतर, रिजर्व बैंक ने मई 2012 में बासल III लागू करने के लिए अंतिम दिशानिर्देश तैयार किए। रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश 1 जनवरी 2013 से लागू होंगे। इस पृष्ठभूमि में, भारतीय बैंकों की विद्यमान पूंजी-स्थिति और सुदृढ़ता संकेतकों की जांच करना महत्वपूर्ण है ताकि बैंकों द्वारा अधिक उन्नत विनियामक स्तरों में अंतरित होने के लिए उनकी तैयारी का आकलन किया जा सके।

### बॉक्स IV.1: भारतीय बैंकों की लाभप्रदता किससे प्रभावित होती है?: बैंक समूहों के लिए डू पॉन्ट विश्लेषण

बैंकों की लाभप्रदता से अनेक बातों की सुविधा हो जाती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने की बैंकों की क्षमता में वृद्धि होना और अनर्जक आस्तियों का बेहतर प्रबंधन शामिल हैं। इसके अलावा, बैंकों की अधिक लाभप्रदता से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया के विस्तार की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पहले की अवधि के दौरान, भारत में बैंक अधिक कड़े विनियमन के माहौल में कार्य कर रहे थे। उदाहरण के बाद, भारतीय बैंक ब्याज दर उदारीकरण के संदर्भ में कम विनियमन, आरक्षित निधि की अपेक्षाओं में कमी और प्रवेश के संबंध में विनियमन हटाने के वातावरण में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही, जटिल वित्तीय उत्पादों के अविष्कार से, हाल के वर्षों में बैंकों का कारोबार पारंपरिक वित्तीय मध्यस्थता प्रक्रिया से आगे निकल चुका है। इसके अतिरिक्त, बैंकों के तुलनपत्र पर एक्सपोजर में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई। इस पृष्ठभूमि में, भारतीय बैंकों की लाभप्रदता के मुख्य स्रोत का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है।

हाल के वर्षों में, बैंक समूहों के बीच लाभप्रदता में काफी अंतर था। यह देखा गया था कि सामान्यतः विदेशी बैंकों की लाभप्रदता अन्य बैंक समूहों की तुलना में अधिक थी। भारतीय बैंकों की लाभप्रदता के संबंध में पहले किए गए कुछ अध्ययनों के अनुसार विदेशी बैंकों की लाभप्रदता अधिक होने का कारण कम लागत की चालू खाता और बचत खाता जमा राशियों तक उनकी पहुंच, आय में विविधता और उच्च 'अन्य आय' कहा जा सकता है। 2011-12 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल निवल लाभ में विदेशी बैंकों का हिस्सा लगभग 12 प्रतिशत था। इसके विपरीत, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में उनका हिस्सा 7 प्रतिशत था (चार्ट 1.क और 1.ख)

बैंक समूहों में लाभप्रदता के स्रोत को समझने के लिए 2011-12 के बैंक समूह-वार आंकड़ों के आधार पर इक्विटी पर आय विश्लेषण और डू पॉन्ट विश्लेषण किए गए। इक्विटी पर आय का विश्लेषण बैंकों की लाभप्रदता को दो घटकों में बांटता है अर्थात्, जैसे कि आस्तियों पर आय और लीवरेज से देखी गयी बैंक आस्तियों की लाभप्रदता और कुल औसत इक्विटी की तुलना में कुल औसत आस्तियों के अनुपात से देखी गयी लाभप्रदता। इसके अलावा, इक्विटी पर

सारणी 1.1: लाभप्रदता का इक्विटी पर आय विश्लेषण: 2011-12

बैंक समूह	इक्विटी पर आय	आस्तियों की लाभप्रदता	लीवरेज	आस्ति-पूंजी अनुपात
1	2	3	4	5
एसबीआई समूह	16	0.91	17.58	0.07
राष्ट्रीयकृत बैंक	15.05	0.87	17.37	0.4
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	15.18	1.15	13.23	0.35
निजी क्षेत्र के नए बैंक	15.27	1.57	9.72	0.27
विदेशी बैंक	10.79	1.75	6.15	6.95

आय के विभाजन से पता चलता है कि बैंकों की लाभप्रदता का संबंध आस्तियों पर उच्च आय से या उच्च लीवरेज से या दोनों से हो सकता है। ऐसे कुछ अध्ययन किए गए हैं जो कि इक्विटी पूंजी को कम लागत के दीर्घकालिक ऋण से प्रतिस्थापित करके इक्विटी पर अधिक आय प्राप्त करने की संभावना पर ध्यान केंद्रित करके किये गये थे। जहां आस्तियों पर उच्च आय को हमेशा अच्छा माना जाता है, वहीं उच्च लीवरेज अनुपात से बैंक के दुर्बल बनने का जोखिम बढ़ता है।

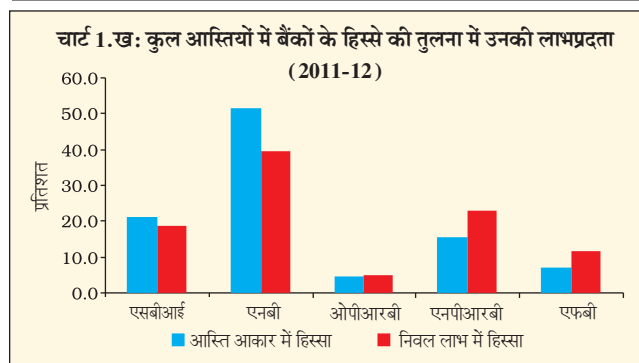
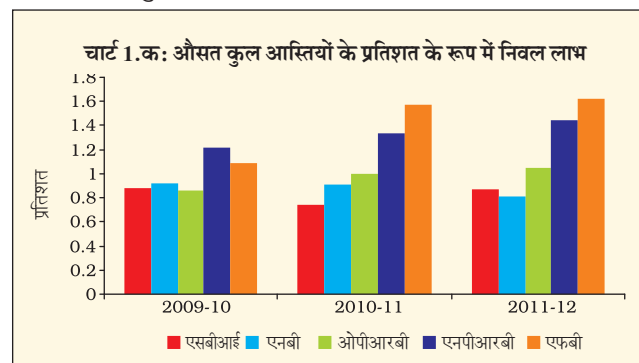
सारणी 1.1 में दिए गए प्रायोगिक परिणामों से यह बात सामने आती है कि एसबीआई समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों का इक्विटी पर उच्च लाभ उच्च लीवरेज अनुपात से संबंधित था जबकि निजी क्षेत्र के नए बैंकों के लिए इक्विटी पर उच्च लाभ आस्तियों की उच्च लाभप्रदता और निम्न लीवरेज से संबंधित था। बैंक समूहों के बीच, विदेशी बैंकों की आस्तियों पर आय अधिक थी और लीवरेज अनुपात कम था। तुलनपत्रीय आंकड़ों का प्रयोग करके विभिन्न बैंक समूहों के संबंध में की गई गणना के अनुसार, आस्ति-पूंजी अनुपात इक्विटी पर आय अनुपात के निष्कर्षों की पुष्टि करता है। मार्च 2012 के अंत में, विदेशी बैंकों के संबंध में यह अनुपात अधिक था जो कि अन्य बैंक समूहों की तुलना में उनकी पूंजी की बेहतर स्थिति को दर्शाता है।

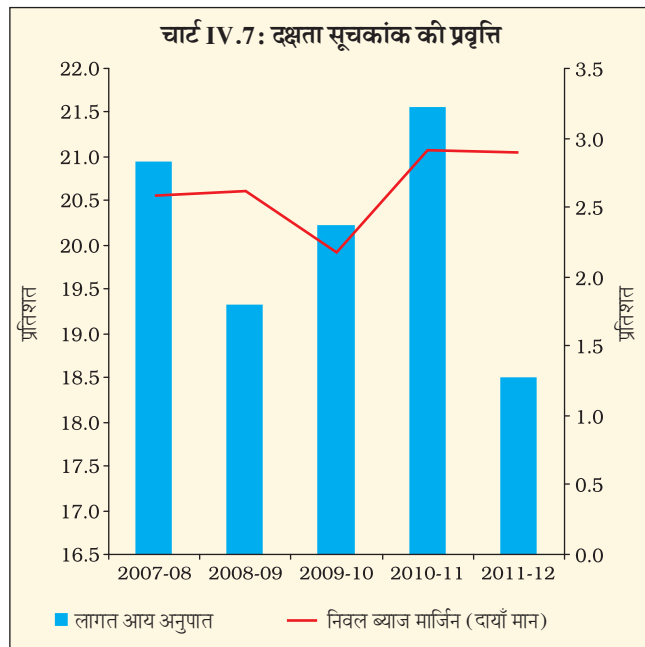
डू पॉन्ट विश्लेषण बैंकों की लाभप्रदता को दो घटकों में बांटता है, नामतः आस्ति उपयोग और लागत प्रबंधन। आस्ति उपयोग की गणना के लिए कुल आय से ब्याज व्यय, और औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधानों/आकस्मिकताओं को घटाया जाता है। औसत कुल आस्ति-परिचालन व्यय अनुपात दर्शाता है कि कोई बैंक अपने संसाधनों को कितने कौशल से प्रयोग में ला रहा है और इस प्रकार यह बैंकों द्वारा लागत प्रबंधन के कौशल को समझने का मानक होता है। बैंकों के बेहतर लाभ का कारण बेहतर आस्ति उपयोग या बेहतर लागत प्रबंधन या एक साथ दोनों हो सकते हैं। नीचे दी गयी सारणी में 2011-12 के लिए बैंकों के संबंध में किए गए डू पॉन्ट विश्लेषण के परिणाम दर्शाए गए हैं।

डू पॉन्ट विश्लेषण के परिणामों के अनुसार, बैंक समूहों के बीच विदेशी बैंकों की आस्तियों पर आय सर्वाधिक थी जिसका मुख्य कारण बेहतर आस्ति उपयोग था, हालांकि उनका आस्ति-परिचालन व्यय अनुपात भी अन्य बैंक समूहों की तुलना में अधिक था। यह परिणाम पुरानी बात की पुष्टि करता है कि विदेशी बैंकों की उच्च लाभप्रदता का कारण बेहतर निधि प्रबंधन प्रथा हो सकता है।

सारणी 2: लाभप्रदता का डू पॉन्ट विश्लेषण: 2011-12

बैंक समूह	आस्तियों पर आय	लागत प्रबंधन
1	2	3
एसबीआई समूह	2.85	1.94
राष्ट्रीयकृत बैंक	2.35	1.48
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	3.06	1.91
निजी क्षेत्र के नए बैंक	3.81	2.24
विदेशी बैंक	4.27	2.52





### पूँजी पर्याप्तता

**बासल I और II के तहत सीआरएआर निर्धारित मानदंडों से पर्याप्त अधिक रहा**

4.25 जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात 2011-12 के दौरान पूरी प्रणाली और सभी बैंक समूहों के संबंध में निर्धारित 9 प्रतिशत से पर्याप्त अधिक रहा जो दर्शाता है कि भारतीय बैंकों की पूँजी-स्थिति अच्छी थी। इसके अलावा, प्रणाली स्तर पर सीआरएआर (बासल II) में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ सुधार हुआ (सारणी IV.12)।

**टियर I पूँजी बैंकों की पूँजी निधि के 70 प्रतिशत से अधिक थी**

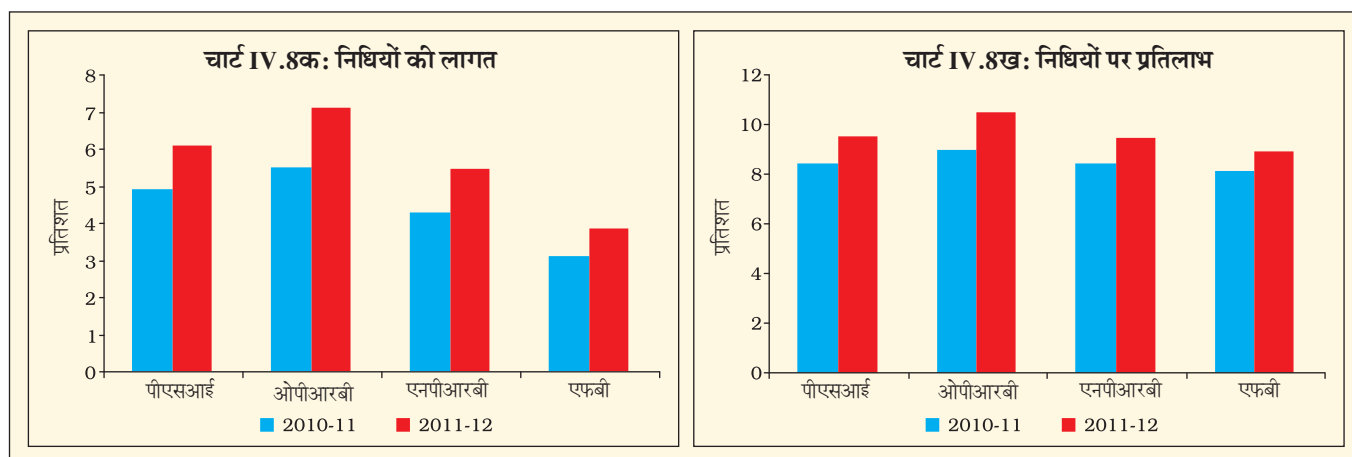
4.26 पूँजी निधि के घटक-वार विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय बैंकों की टियर I पूँजी बासल I और बासल II के तहत

**सारणी IV.11: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल - बैंक समूह-वार**

									(प्रतिशत)
क्र. सं.	बैंक समूह / वर्ष	जमा की लागत	उधार की लागत	निधि की लागत	अग्रिमों पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	निधि पर प्रतिफल	अंतर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-5)	
<b>1</b>	<b>सरकारी क्षेत्र के बैंक</b>								
	<b>2010-11</b>	<b>5.12</b>	<b>2.28</b>	<b>4.89</b>	<b>9.09</b>	<b>6.80</b>	<b>8.41</b>	<b>3.52</b>	
	<b>2011-12</b>	<b>6.36</b>	<b>2.81</b>	<b>6.06</b>	<b>10.30</b>	<b>7.54</b>	<b>9.52</b>	<b>3.46</b>	
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक*								
	2010-11	5.13	2.36	4.93	9.21	6.83	8.49	3.56	
	2011-12	6.51	2.78	6.22	10.32	7.44	9.49	3.27	
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह								
	2010-11	5.09	2.14	4.79	8.84	6.72	8.22	3.43	
	2011-12	5.97	2.85	5.66	10.26	7.78	9.59	3.93	
<b>2</b>	<b>निजी क्षेत्र के बैंक</b>								
	<b>2010-11</b>	<b>4.97</b>	<b>2.33</b>	<b>4.56</b>	<b>9.65</b>	<b>6.53</b>	<b>8.55</b>	<b>3.99</b>	
	<b>2011-12</b>	<b>6.43</b>	<b>2.92</b>	<b>5.84</b>	<b>10.99</b>	<b>7.26</b>	<b>9.69</b>	<b>3.85</b>	
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक								
	2010-11	5.63	2.24	5.50	10.42	6.20	8.98	3.48	
	2011-12	7.24	4.34	7.10	11.98	7.37	10.47	3.37	
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक								
	2010-11	4.73	2.33	4.27	9.41	6.62	8.42	4.15	
	2011-12	6.14	2.81	5.45	10.69	7.23	9.46	4.01	
<b>3</b>	<b>विदेशी बैंक</b>								
	<b>2010-11</b>	<b>3.30</b>	<b>2.56</b>	<b>3.11</b>	<b>8.75</b>	<b>7.39</b>	<b>8.11</b>	<b>5.00</b>	
	<b>2011-12</b>	<b>4.34</b>	<b>2.60</b>	<b>3.83</b>	<b>9.61</b>	<b>8.10</b>	<b>8.91</b>	<b>5.08</b>	
<b>4</b>	<b>सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक</b>								
	<b>2010-11</b>	<b>5.01</b>	<b>2.33</b>	<b>4.73</b>	<b>9.18</b>	<b>6.79</b>	<b>8.42</b>	<b>3.69</b>	
	<b>2011-12</b>	<b>6.28</b>	<b>2.81</b>	<b>5.90</b>	<b>10.40</b>	<b>7.53</b>	<b>9.52</b>	<b>3.62</b>	

**टिप्पणियाँ:** 1. जमा की लागत = जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पिछले वर्ष की जमा राशियों का औसत।  
 2. उधारों की लागत = उधारों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पिछले वर्ष के उधारों का औसत।  
 3. निधियों की लागत = (जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज + उधारों पर अदा किया गया ब्याज) / (चालू और पिछले वर्ष की जमा राशियों + उधारों का औसत)।  
 4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / चालू और पिछले वर्ष के अग्रिमों का औसत।  
 5. निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज / चालू और पिछले वर्ष के निवेशों का औसत।  
 6. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेशों पर अर्जित ब्याज) / (चालू और पिछले वर्ष के अग्रिमों + निवेशों का औसत)।  
 7. \*: \*आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

**स्रोत:** संबंधित बैंकों के तुलना पत्रों से परिकलित।



उनकी कुल पूंजी के 70 प्रतिशत से अधिक थी। मार्च 2012 के अंत में, कोर सीआरएआर न्यूनतम 6 प्रतिशत के निर्धारण से काफी अधिक था (सारणी IV.13)।

**सरकारी क्षेत्र के अधिकतर बैंकों ने 8 प्रतिशत से अधिक का टियर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात रिपोर्ट किया**

4.27 मार्च 2012 के अंत में, सरकारी क्षेत्र के अधिकतर बैंकों का टियर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8 से 12 प्रतिशत के दायरे में था (चार्ट IV.9)।

**सारणी IV.12: बासेल I और II के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - बैंक समूह-वार (मार्च अंत की स्थिति)**

(प्रतिशत)

मद	बासेल I		बासेल II	
	2011	2012	2011	2012
बैंक समूह	2	3	4	5
1				
<b>सरकारी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>11.78</b>	<b>11.88</b>	<b>13.08</b>	<b>13.23</b>
राष्ट्रीयकृत बैंक*	12.15	11.84	13.47	13.03
भारतीय स्टेट बैंक समूह	11.01	11.97	12.25	13.70
<b>निजी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>15.15</b>	<b>14.47</b>	<b>16.46</b>	<b>16.21</b>
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	13.29	12.47	14.55	14.12
निजी क्षेत्र के नए बैंक	15.55	14.90	16.87	16.66
<b>विदेशी बैंक</b>	<b>17.71</b>	<b>17.31</b>	<b>16.97</b>	<b>16.74</b>
<b>अनुसूचित वाणिज्य बैंक</b>	<b>13.02</b>	<b>12.94</b>	<b>14.19</b>	<b>14.24</b>

टिप्पणी : \*: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल है।

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।

**सारणी IV.13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घटकवार पूंजी पर्याप्तता (मार्च अंत की स्थिति)**

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	बासेल I		बासेल II	
	2011	2012	2011	2012
<b>1. पूंजी निधियां (i+ii)</b>	<b>6,745</b>	<b>7,810</b>	<b>6,703</b>	<b>7,780</b>
i) टियर I पूंजी	4,765	5,685	4,745	5,672
ii) टियर II पूंजी	1,980	2,124	1,958	2,109
<b>2. जोखिम भारित आस्तियां</b>	<b>51,807</b>	<b>60,375</b>	<b>47,249</b>	<b>54,623</b>
<b>3. सीआरएआर (ख के % के रूप में क)</b>	<b>13.0</b>	<b>12.9</b>	<b>14.2</b>	<b>14.2</b>
जिसमें से: टियर I	9.2	9.4	10.0	10.4
टियर II	3.8	3.5	4.1	3.9

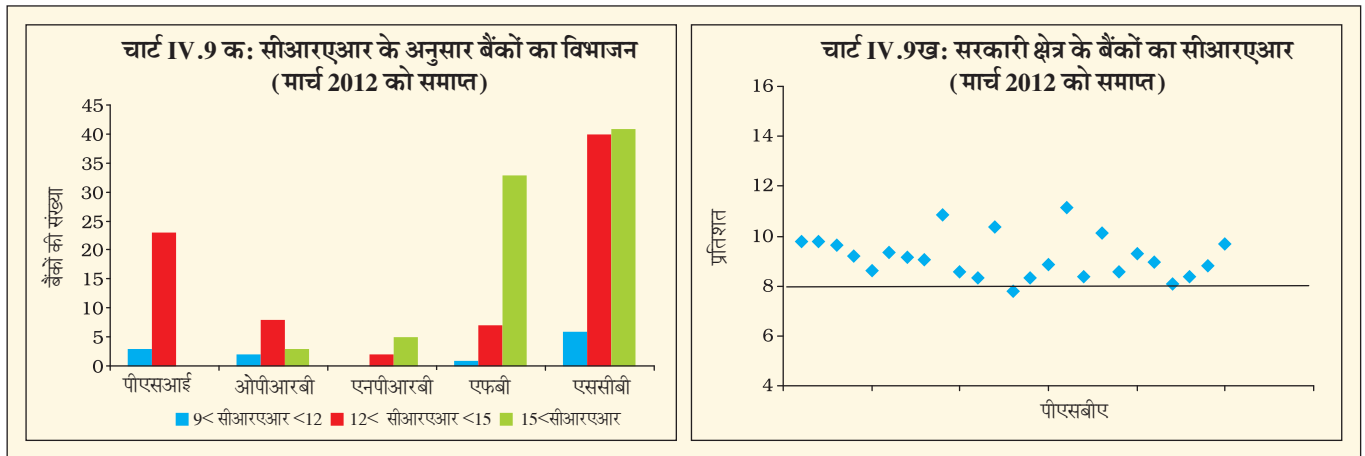
स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।

**लीवरेज अनुपात**

**लीवरेज अनुपात 4.5 प्रतिशत से काफी अधिक बना रहा**

4.28 2011-12 में टियर I पूंजी (बासेल II के तहत) के रूप में गणना किया गया लीवरेज अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया और 4.5 प्रतिशत<sup>3</sup> से ऊपर बना रहा जो कि भारतीय बैंकों की पूंजी की स्थिति में सुधार दर्शाता है। यह बात सीआरएआर (बासेल II के तहत) में हुई वृद्धि के अनुरूप ही थी (चार्ट IV.10)

<sup>3</sup> बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार, लीवरेज अनुपात के लिए सांविधिक न्यूनतम स्तर 4.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया।



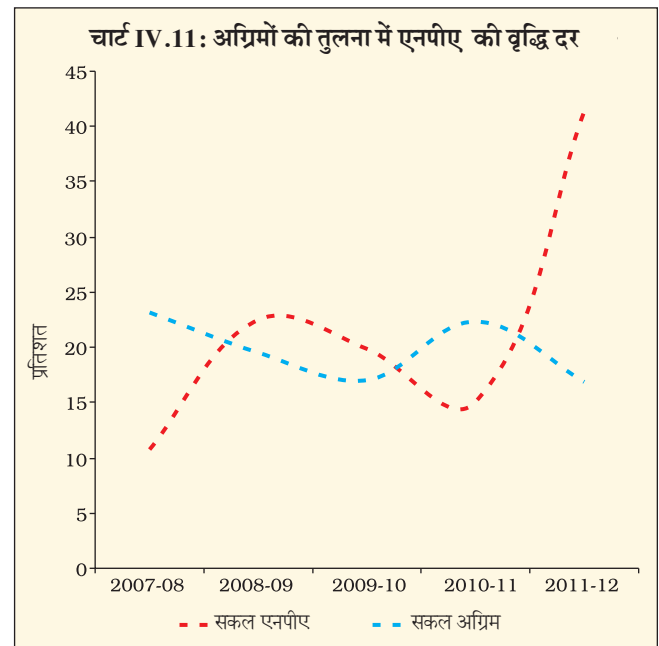
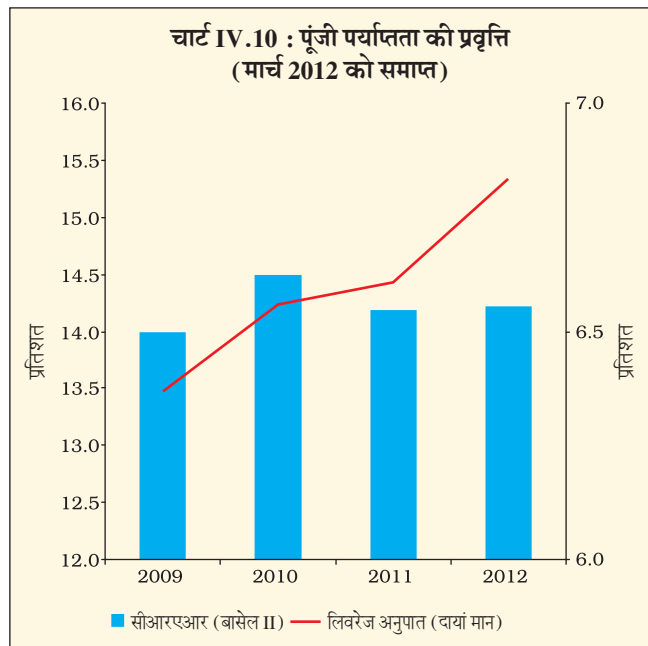
**अनर्जक आस्तियां**

**प्रणाली स्तर पर सकल एनपीए अनुपात में सुधार हुआ जिसका मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता कम हो जाना था**

4.29 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में कमी आना प्रमुख चिंता के रूप में उभरा जिसमें बैंकों के सकल एनपीए

में तेज वृद्धि हुई थी। एनपीए में तेज वृद्धि का कारण देशी अर्थव्यवस्था में नरमी और ऋण प्रस्तावों का अपर्याप्त आकलन तथा निगरानी कहा जा सकता है (चार्ट IV.11)।<sup>4</sup>

4.30 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में अधिक कमी आयी थी। 2011-12 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए प्रणाली स्तरीय एनपीए की वृद्धि दर से अधिक दर पर बढ़ा (सारणी IV.14 और चार्ट IV.12)।



<sup>4</sup> सकल अनर्जक आस्तियों और अग्रिमों की वृद्धि दर की गणना आफसाइट विवरणियों के आधार पर की गई।

सारणी IV.14: अनर्जक आस्तियों की प्रवृत्ति - बैंक समूह-वार

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>सकल एनपीए</b>								
2010-11 के लिए अंतिम शेष	746	442	303	182	36	145	50	979
2011-12 का प्रारंभिक शेष	746	442	303	182	36	145	50	979
2011-12 के दौरान जोड़	928	586	341	98	27	71	45	1,071
2011-12 के दौरान वसूली	478	325	152	73	20	52	32	585
2011-12 के दौरान बढ़ा खाता डाले गए	23	13	10	19	1	18	-	43
2011-12 का अंतिम शेष	1,172	690	482	187	42	145	62	1,423
<b>सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए**</b>								
2010-11	2.4	2.1	3.4	2.5	1.9	2.7	2.5	2.5
2011-12	3.3	2.8	4.6	2.1	1.8	2.2	2.6	3.1
<b>निवल एनपीए</b>								
2010-11 का अंतिम शेष	360	212	147	44	9	34	12	417
2011-12 का अंतिम शेष	591	389	202	44	13	30	14	649
<b>निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए***</b>								
2010-11	1.2	1.0	1.7	0.6	0.5	0.6	0.6	1.1
2011-12	1.7	1.6	2.0	0.5	0.6	0.5	0.6	1.4

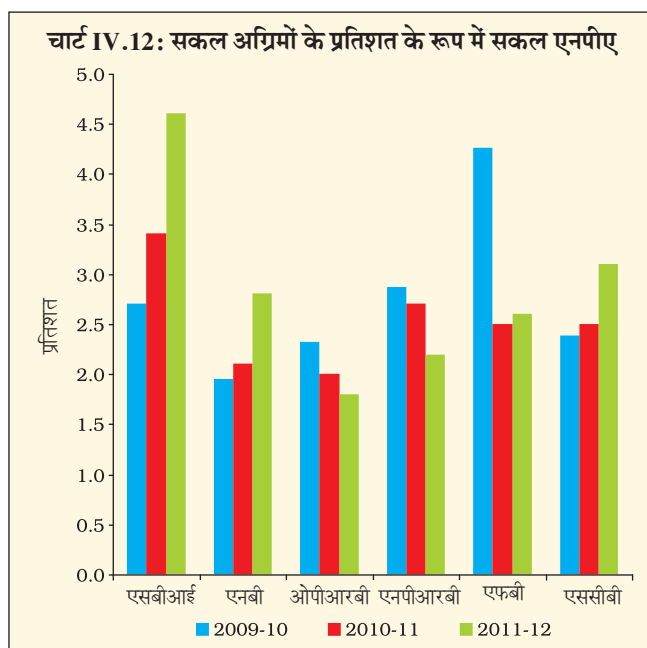
टिप्पणी : 1.\*: आईडीबीआई बैंक लि. सहित।

2.\*\*: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे से सकल अनर्जक आस्तियों तथा ऑफ साइट विवरणियों से सकल अग्रिमों की गणना की जाती है।

3.\*\*\*: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे से निवल अनर्जक आस्तियों तथा ऑफ साइट विवरणियों से सकल अग्रिम लेकर गणना की गयी है।

4.-: कुछ नहीं/नगण्य

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।



स्लिपेज अनुपात की स्थिति खराब हुई, हालांकि वसूली अनुपात में सुधार हुआ

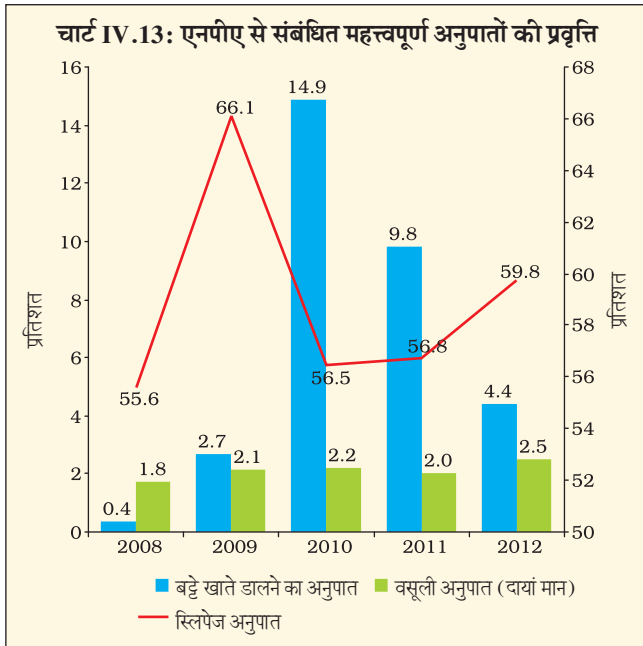
4.31 प्रणाली स्तर पर सकल एनपीए में वृद्धि होने के अलावा, स्लिपेज अनुपात<sup>5</sup> से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में नए एनपीए में भी वृद्धि हुई है। किंतु एक सकारात्मक बात यह है कि वर्ष के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के वसूली अनुपात<sup>6</sup> में सुधार हुआ है। 2011-12 के दौरान, बढ़ा खाता अनुपात<sup>7</sup> पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम था (चार्ट IV.13)।

4.32 बैंक समूह स्तर पर, स्लिपेज अनुपात से पता चलता है कि एनपीए में वृद्धि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में अधिक थी। किंतु उनका वसूली निष्पादन भी निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में बेहतर था। विभिन्न बैंक समूहों के बीच, निजी क्षेत्र के नए बैंक अपने एनपीए के स्तर को नियंत्रित रखने

5 स्लिपेज अनुपात को वर्ष के प्रारंभ में मानक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों में हुई नई वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है।

6 वसूली अनुपात को वर्ष के प्रारंभ में बकाया सकल अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान वसूली गई अनर्जक आस्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

7 बढ़ा खाता अनुपात को वर्ष के प्रारंभ में बकाया सकल अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान बढ़ा खाते में डाली गई अनर्जक आस्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है।



के उपाय के रूप में एनपीए को बट्टे खाते डालने पर अधिक निर्भर थे (चार्ट IV.14)।

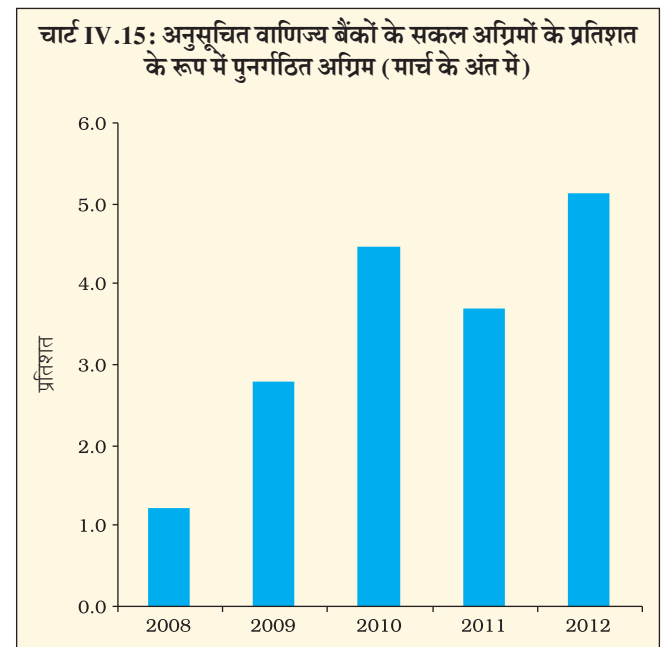
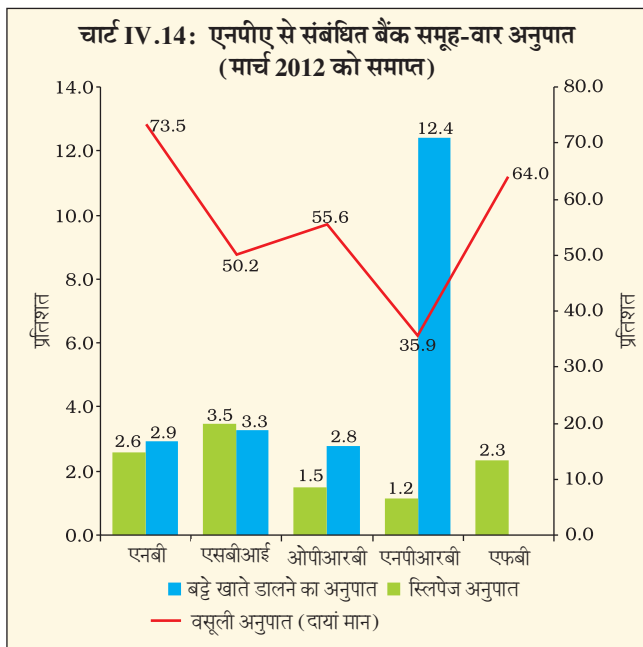
### पुनर्निर्धारित मानक अग्रिमों में काफी वृद्धि हुई

4.33 हाल के वर्षों में, बढ़ते एनपीए के कारण आस्ति गुणवत्ता का कम होना रोकने के लिए बैंकों द्वारा प्रयोग किया जा रहा एक महत्वपूर्ण उपाय अग्रिमों का पुनर्निर्धारण है। देशी अर्थव्यवस्था

में नरमी के कारण बैंकों और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 2008 में घोषित रिजर्व बैंक की विशेष राहत योजना के तहत अपने अग्रिमों को पुनर्निर्धारित करने का सक्रिय रूप से सहारा लिया। इस योजना से पुनर्निर्धारण के बाद भी मानक खातों का स्टेटस बनाए रखना बैंकों के लिए आसान रहा। 2011-12 के दौरान सकल एनपीए में तेज वृद्धि के साथ पुनर्निर्धारित अग्रिमों में भी तेज वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विशेष रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पुनर्निर्धारित किए गए अग्रिमों में तेज वृद्धि होना था (चार्ट IV.15 और IV.16)।

4.34 2011-12 के दौरान, वित्तीय आस्ति प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और लोक अदालत के माध्यम से वसूले गए एनपीए की कुल राशि में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आयी। इन चैनलों के माध्यम से वसूली गयी कुल राशि में सरफेसी अधिनियम के माध्यम से वसूली गयी राशि लगभग 70 प्रतिशत थी।

4.35 सरफेसी अधिनियम के माध्यम से अशोध्य ऋणों की पूरी वसूली न होने पर बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संपर्क करते हैं। वर्तमान में, देश में 33 ऋण वसूली न्यायाधिकरण और पांच ऋण वसूली अपीलेट न्यायाधिकरण हैं। इन तीन चैनलों के



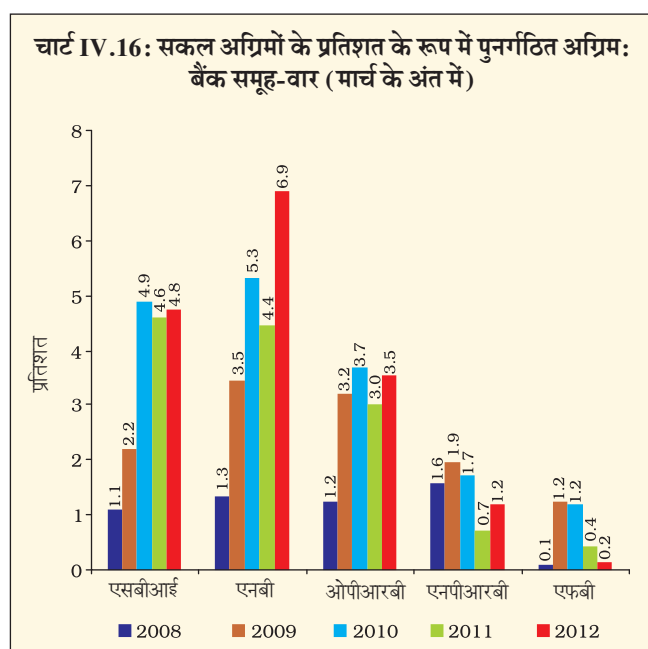
**सारणी IV.15: विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूले गए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एनपीए**

(राशि ₹ बिलियन में)

वसूली चैनल	2010-11				2011-12			
	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली की राशि*	स्तंभ (3) के % के रूप में स्तंभ (4)	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि*	स्तंभ (7) के % के रूप में स्तंभ (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) लोक अदालत	6,16,018	53	2	3.7	4,76,073	17	2	11.8
ii) डीआरटी	12,872	141	39	27.6	13,365	241	41	17.0
iii) सरफेसी अधिनियम	1,18,642#	306	116	37.9	1,40,991#	353	101	28.6
<b>कुल</b>	<b>7,47,532</b>	<b>500</b>	<b>157</b>	<b>31.4</b>	<b>6,30,429</b>	<b>611</b>	<b>144</b>	<b>23.6</b>

**टिप्पणियाँ:** 1. \*: दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि, जो दिए गए वर्ष के दौरान और पूर्व वर्षों के दौरान भेजे गए मामलों के संबंध में हो सकती है।  
2. #: भेजी गई नोटिसों की संख्या

**चार्ट IV.16: सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुनर्गठित अग्रिम बैंक समूह-वार (मार्च के अंत में)**



माध्यम से वसूले गए कुल एनपीए में ऋण वसूली न्यायाधिकरण के माध्यम से लगभग 28 प्रतिशत एनपीए की वसूली हुई थी (सारणी IV.15)।

4.36 जून 2012 के अंत में, 14 प्रतिभूतीकरण/ पुनर्गठन कंपनियों द्वारा जारी कुल प्रतिभूति प्राप्तियों में लगभग 70 प्रतिशत अभिदान बैंकों द्वारा किया गया था। सरफेसी अधिनियम के तहत कार्य करने वाली ये कंपनियां बैंकों से एनपीए बट्टाकृत मूल्य पर प्राप्त करती हैं जिससे बैंकिंग क्षेत्र को अपने तुलनपत्रों की स्थिति सुधारने में सहायता मिलती है (सारणी IV.16)।

**प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में गिरावट आयी**

4.37 एनपीए में हुई उच्च वृद्धि के अनुरूप कुल प्रावधानीकरण में भी उच्च दर पर वृद्धि होने के बावजूद प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आयी। इसका मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में गिरावट आना था (सारणी IV.17)।

**निवल आस्तियों में काफी वृद्धि हुई**

4.38 सकल एनपीए वृद्धि बढ़ने के अनुरूप और प्रावधानीकरण के कम कवरेज के कारण निवल एनपीए में उच्च वृद्धि हुई। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निवल एनपीए अधिक था (सारणी IV.14 भी देखें)।

**सारणी IV.16: एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों का विवरण**

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च 2012 के अंत में	जून 2012 के अंत में
1	2	3
1 अर्जित आस्तियों का बही मूल्य	769	805
2 एससी/आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें	165	167
3 निम्नलिखित के द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदें		
(अ) बैंक	115	116
(ब) एससी /आरसी	35	36
(क) एफआईआई	1	1
(ड) अन्य (अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता)	14	15
4 पूरी तरह से शोधित प्रतिभूति रसीदों की राशि	79	82

**स्रोत :** प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण।



**सारणी IV.17: अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की प्रवृत्तियां - बैंक समूह-वार**

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक*	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>एनपीए के लिए प्रावधान</b>								
मार्च 2011 के अंत में	366	212	154	135	24	110	38	540
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	381	219	161	56	8	47	34	472
घटाएँ: बड़ा खाते डाले गए, वर्ष के दौरान अधिक के प्रतिलेखन	190	152	38	51	7	43	23	264
मार्च 2012 के अंत में	558	279	278	140	25	114	49	747
<i>जापान: प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (सकल एनपीए की तुलना में बकाया प्रावधानों का अनुपात (प्रतिशत))</i>								
मार्च 2011 के अंत में	49.0	47.9	50.7	74.0	64.9	75.6	75.0	55.1
मार्च 2012 के अंत में	47.6	40.4	57.7	74.9	61.0	78.6	79.0	52.5

टिप्पणी: \*: आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

**एनपीए अधिक दृढ़ हो गए जिनमें सकल अग्रियों में अवमानक और संदिग्ध आस्तियों का अनुपात बढ़ रहा है**

4.39 एनपीए में वृद्धि के अलावा, कुल सकल अग्रियों के प्रतिशत के रूप में अवमानक/संदिग्ध आस्तियों में

वृद्धि के रूप में आस्ति गुणवत्ता में कमी आना भी स्पष्ट हो रहा है। कुल सकल अग्रियों के प्रतिशत के रूप में इन दो श्रेणियों में वृद्धि होना दर्शाता है कि एनपीए दृढ़ हो गए हैं (सारणी IV.18)।

**सारणी IV.18: ऋण आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूह-वार**

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

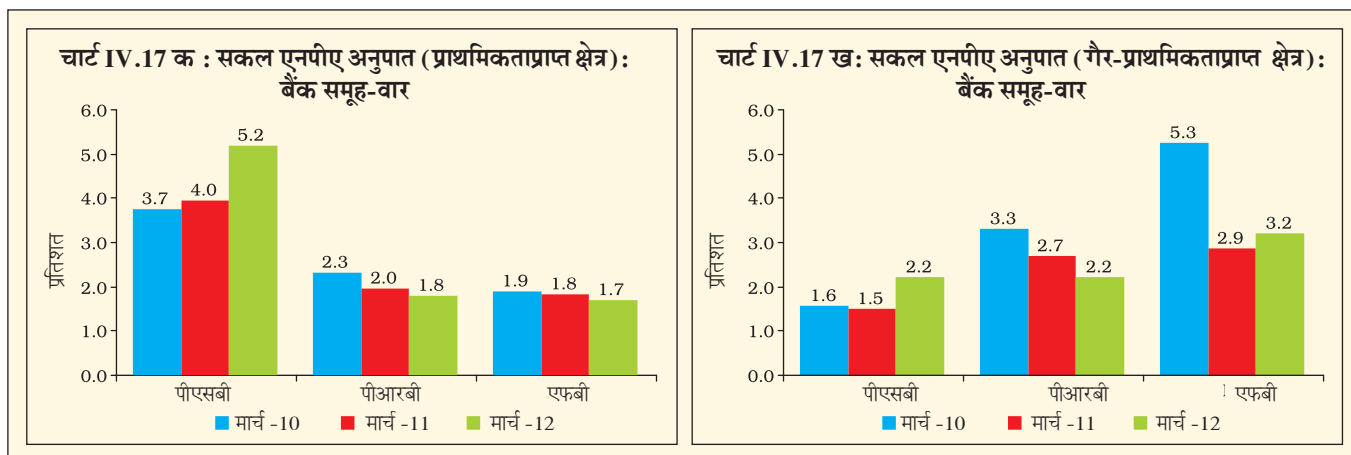
क्र. सं.	बैंक समूह	वर्ष	मानक आस्तियां		अवमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
			राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>सरकारी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>2011</b>	<b>32,718</b>	<b>97.8</b>	<b>350</b>	<b>1.0</b>	<b>332</b>	<b>1.0</b>	<b>65</b>	<b>0.2</b>
		<b>2012</b>	<b>38,255</b>	<b>97.0</b>	<b>623</b>	<b>1.6</b>	<b>490</b>	<b>1.2</b>	<b>60</b>	<b>0.2</b>
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक**	2011	22,900	98.1	218	0.9	193	0.8	32	0.1
		2012	26,910	97.5	402	1.5	268	1.0	21	0.1
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	2011	9,818	97.0	132	1.3	139	1.4	33	0.3
		2012	11,345	95.9	221	1.9	222	1.9	39	0.3
<b>2</b>	<b>निजी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>2011</b>	<b>7,936</b>	<b>97.8</b>	<b>45</b>	<b>0.6</b>	<b>108</b>	<b>1.3</b>	<b>29</b>	<b>0.4</b>
		<b>2012</b>	<b>9,629</b>	<b>98.1</b>	<b>52</b>	<b>0.5</b>	<b>104</b>	<b>1.1</b>	<b>29</b>	<b>0.3</b>
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2011	1,836	98.0	13	0.7	18	1.0	6	0.3
		2012	2,287	98.2	18	0.8	17	0.7	7	0.3
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	2011	6,100	97.7	33	0.5	90	1.4	22	0.4
		2012	7,342	98.1	34	0.4	87	1.2	22	0.3
<b>3</b>	<b>विदेशी बैंक</b>	<b>2011</b>	<b>1,943</b>	<b>97.5</b>	<b>19</b>	<b>0.9</b>	<b>21</b>	<b>1.1</b>	<b>11</b>	<b>0.5</b>
		<b>2012</b>	<b>2,284</b>	<b>97.3</b>	<b>21</b>	<b>0.9</b>	<b>22</b>	<b>0.9</b>	<b>20</b>	<b>0.8</b>
<b>4.</b>	<b>अनुसूचित वाणिज्य बैंक</b>	<b>2011</b>	<b>42,596</b>	<b>97.8</b>	<b>414</b>	<b>0.9</b>	<b>461</b>	<b>1.1</b>	<b>104</b>	<b>0.2</b>
		<b>2012</b>	<b>50,168</b>	<b>97.2</b>	<b>695</b>	<b>1.3</b>	<b>617</b>	<b>1.2</b>	<b>109</b>	<b>0.2</b>

टिप्पणियाँ: 1. पूर्णांकन के कारण घटक मदों के जोड़ में अंतर हो सकता है।

2. \*: सकल अग्रियों के प्रतिशत के रूप में।

3. \*\*: आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां।



### अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार विश्लेषण<sup>8</sup>

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में आयी कमी प्राथमिकताप्राप्त और गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों तक बढ़ गयी**

4.40 सकल अग्रिम-सकल एनपीए अनुपात का बैंक समूह-वार विश्लेषण दर्शाता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह अनुपात प्राथमिकताप्राप्त और गैर-प्राथमिकताप्राप्त दोनों क्षेत्रों तक बढ़ गया। इसके अलावा, सकल अग्रिम-सकल एनपीए अनुपात (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र) भी अन्य बैंक समूहों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में काफी अधिक था (चार्ट IV.17)।

### कुल में से लगभग आधे एनपीए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के थे

4.41 2011-12 के दौरान, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की कुल अनर्जक आस्तियां प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण की वृद्धि दर की तुलना में अधिक दर पर बढ़ीं। किंतु कुल अनर्जक आस्तियों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया। बैंक समूहों के बीच, कुल अनर्जक आस्तियों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का अनुपात सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में अधिक था।

### कुल एनपीए में कृषि क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि हुई

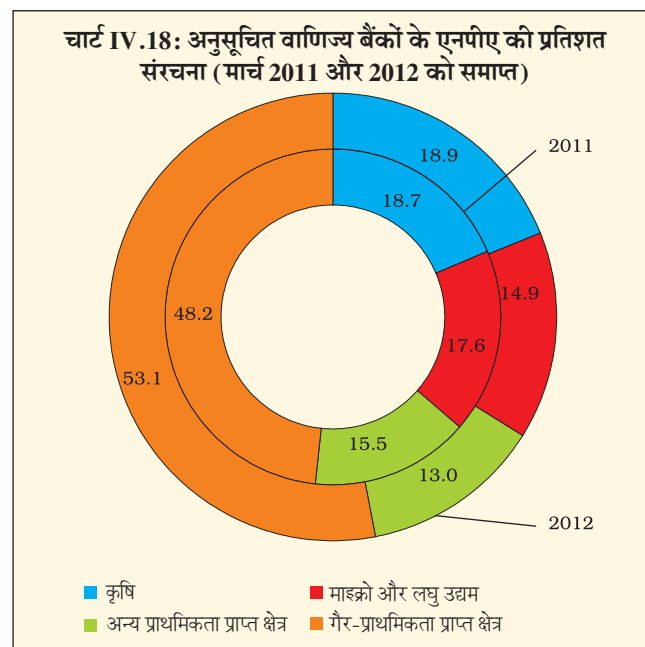
4.42 एनपीए के क्षेत्र-वार वर्गीकरण से पता चला कि 2011-12 के दौरान कुल एनपीए में कृषि का हिस्सा कुछ बढ़ गया था। किंतु मंद औद्योगिक निष्पादन के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र के कुल

एनपीए में अति लघु और लघु उद्यमों का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया (चार्ट IV.18 और सारणी IV.19)।

### चलनिधि

### चलनिधि अनुपात में कुछ गिरावट आयी

4.43 2011-12 में, बैंकों की चलनिधि पर अनेक संरचनात्मक आदि कारकों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिनमें अन्य के साथ ही जमाराशि वृद्धि दर में गिरावट, आस्ति और देयता की अवधिपूर्णाता प्रोफाइल में बढ़ता असंतुलन और दीर्घकालिक



<sup>8</sup> इस खंड का विश्लेषण ऑफसाइट विवरणियों से संग्रहीत आंकड़ों पर आधारित है।

**सारणी IV.19: देशी बैंकों का क्षेत्रवार एनपीए\***

(राशि ₹ बिलियन में)

बैंक समूह	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		जिसमें से						गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		जिसमें से		कुल एनपीए	
			कृषि		माइक्रो तथा लघु उद्यम		अन्य							
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
<b>सरकारी क्षेत्र के बैंक</b>														
<b>2011</b>	<b>413</b>	<b>58.1</b>	<b>145</b>	<b>20.4</b>	<b>144</b>	<b>20.2</b>	<b>124</b>	<b>17.5</b>	<b>298</b>	<b>41.9</b>	<b>3</b>	<b>0.4</b>	<b>711</b>	<b>100.0</b>
<b>2012</b>	<b>562</b>	<b>50.0</b>	<b>227</b>	<b>20.1</b>	<b>178</b>	<b>15.9</b>	<b>157</b>	<b>14.0</b>	<b>563</b>	<b>50.0</b>	<b>32</b>	<b>2.9</b>	<b>1,125</b>	<b>100.0</b>
राष्ट्रीयकृत बैंक**														
2011	257	59.9	92	21.5	105	24.4	60	14.0	172	40.1	3	0.6	430	100.0
2012	323	48.3	129	19.3	134	20.0	61	9.1	345	51.7	10	1.5	668	100.0
भारतीय स्टेट बैंक समूह														
2011	156	55.3	53	18.7	39	13.9	64	22.7	126	44.7	-	0	281	100.0
2012	239	52.3	98	21.4	45	9.8	97	21.1	218	47.7	22	4.9	457	100.0
<b>निजी क्षेत्र के बैंक</b>														
<b>2011</b>	<b>48</b>	<b>26.8</b>	<b>22</b>	<b>12.1</b>	<b>13</b>	<b>7.2</b>	<b>14</b>	<b>7.5</b>	<b>132</b>	<b>73.2</b>	<b>2</b>	<b>0.8</b>	<b>180</b>	<b>100.0</b>
<b>2012</b>	<b>51</b>	<b>27.9</b>	<b>22</b>	<b>11.8</b>	<b>17</b>	<b>9.4</b>	<b>12</b>	<b>6.7</b>	<b>132</b>	<b>72.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>100.0</b>
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक														
2011	16	43.3	4	11.3	6	14.9	6	17.1	21	56.7	2	4.1	37	100.0
2012	18	42.9	6	13.4	7	16.8	5	12.8	24	57.1	0	0	42	100.0
निजी क्षेत्र के नए बैंक														
2011	32	22.6	18	12.3	8	5.2	7	5.1	111	77.4	0	0	143	100.0
2012	33	23.4	16	11.3	10	7.1	7	4.9	108	76.6	0	0	141	100.0
<b>सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक</b>														
<b>2011</b>	<b>461</b>	<b>51.8</b>	<b>167</b>	<b>18.7</b>	<b>157</b>	<b>17.6</b>	<b>138</b>	<b>15.5</b>	<b>430</b>	<b>48.2</b>	<b>4</b>	<b>0.5</b>	<b>891</b>	<b>100.0</b>
<b>2012</b>	<b>613</b>	<b>46.9</b>	<b>248</b>	<b>19.0</b>	<b>195</b>	<b>14.9</b>	<b>169</b>	<b>13.0</b>	<b>695</b>	<b>53.1</b>	<b>32</b>	<b>2.5</b>	<b>1,308</b>	<b>100.0</b>

**टिप्पणी:** 1. \*: विदेशी बैंक शामिल नहीं।  
 2. -: शून्य / नगण्य  
 3. प्रतिशत - कुल एनपीए का प्रतिशत।  
 4. \*\*: आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

**स्रोत:** बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों (देशी) पर आधारित।

आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के प्रति एक्सपोजर शामिल हैं। कुल आस्तियों में चलनिधि आस्तियों (रिजर्व बैंक में सीआरआर संबंधी अपेक्षा से अधिक रखी हुई नकदी और शेष, और एक वर्ष तक की अवधिपूर्णता के निवेश और अग्रिम) को बैंकों की चलनिधि की स्थिति की सामान्य माप माना जा सकता है। 2011-12 के दौरान इस अनुपात में कुछ गिरावट आयी।

**5. बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन**

**कुल खाद्येतर बैंक ऋण वृद्धि में गिरावट हुई**

4.44 2011-12 में कुल खाद्येतर बैंक ऋण वृद्धि में गिरावट आई। यह प्रवृत्ति बैंकों के समेकित तुलनपत्र में ऋण और अग्रिमों की वृद्धि में देखी गयी समग्र नरमी के अनुरूप ही थी। देशी अर्थव्यवस्था का वृद्धि निष्पादन चक्रीय और संरचनात्मक कारकों के कारण मंद रहा जो कि आंशिक रूप से ऋण लेने में नरमी आने का संकेत देता है। 2011-12 में खाद्येतर बैंक ऋण वृद्धि

में समग्र गिरावट मुख्यतः उद्योगों को ऋण और सेवाओं को ऋण तथा निजी ऋण के कारण हुई थी।

4.45 अधिकतर निजी ऋणों का स्वरूप दीर्घकालिक होता है, अतः निजी ऋणों में वृद्धि, विशेष रूप से 2011-12 में एनपीए में हुई वृद्धि की पृष्ठभूमि में, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। निजी ऋण की वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में कम हुई। निजी ऋण घटक के अंतर्गत आवास ऋण में कमी आयी (सारणी IV.20)।

**बुनियादी सुविधा ऋण की गति धीमी रही**

4.46 ऋण वृद्धि में समग्र गिरावट के कारण बुनियादी सुविधा ऋण में भी नरमी रही। मार्च 2012 के अंत में, कुल बुनियादी सुविधा ऋण में बिजली क्षेत्र का हिस्सा आधे से अधिक था (चार्ट IV.19)। इसके साथ ही, बिजली क्षेत्र को ऋण में वृद्धि बुनियादी सुविधा क्षेत्र को हुई ऋण वृद्धि की तुलना में अधिक थी। इसके

**सारणी IV.20 : सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन**

(राशि ₹ बिलियन में)

क्रम सं.	क्षेत्र	को बकाया		प्रतिशत घट-बढ़	
		मार्च-11	मार्च-12	2010-11	2011-12
1	<b>कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां</b>	<b>4,603</b>	<b>5,226</b>	<b>10.6</b>	<b>13.5</b>
2	<b>उद्योग, जिसमें से</b>	<b>16,208</b>	<b>19,659</b>	<b>23.6</b>	<b>21.3</b>
	2.1 मूलभूत सुविधाएं	5,266	6,191	38.6	17.6
	2.2 माइक्रो तथा लघु उद्योग	2,291	2,592	11.0	13.1
3	<b>सेवाएं</b>	<b>9,008</b>	<b>10,330</b>	<b>23.9</b>	<b>14.7</b>
	3.1 व्यापार	1,863	2,209	13.2	18.6
	3.2 वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र	1,118	1,205	21.4	7.8
	3.3 पर्यटन, होटल तथा रेस्तराँ	277	313	42.9	12.9
	3.4 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	151	154	20.3	2.1
	3.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	1,756	2,218	54.8	26.3
4	<b>व्यक्तिगत ऋण</b>	<b>6,854</b>	<b>7,683</b>	<b>17.0</b>	<b>12.1</b>
	4.1 क्रेडिट कार्ड बकाया	181	204	-10.2	12.9
	4.2 शिक्षा	437	502	18.6	14.8
	4.3 आवास (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आवास सहित)	3,461	3,880	15.0	12.1
	4.4 सावधि जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम (एफसीएनआर (बी), एनआरएनआर जमाराशियां आदि सहित)	605	685	24.4	13.2
5	<b>कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण</b>	<b>36,674</b>	<b>42,897</b>	<b>20.6</b>	<b>17.0</b>
6	<b>कुल सकल बैंक ऋण</b>	<b>37,315</b>	<b>43,714</b>	<b>20.8</b>	<b>17.1</b>

**टिप्पणी:** 1. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।  
2. बिलियन की संख्याओं के पूर्णांकन के कारण घटकों में अंतर हो सकता है।

**स्रोत:** बैंक ऋण विवरणी (मासिक) का क्षेत्रवार और औद्योगिक अभिनियोजन।

अलावा, बिजली क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के बैंक की आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव, और विशेष रूप से इस क्षेत्र में हाल की अवधि में देखी गयी नरमी को ध्यान में रखकर, उसकी निगरानी की आवश्यकता है। इसके अलावा, बुनियादी सुविधा क्षेत्र को ऋण दीर्घकालिक स्वरूप का होने के कारण इससे अवधिपूर्णता संबंधी

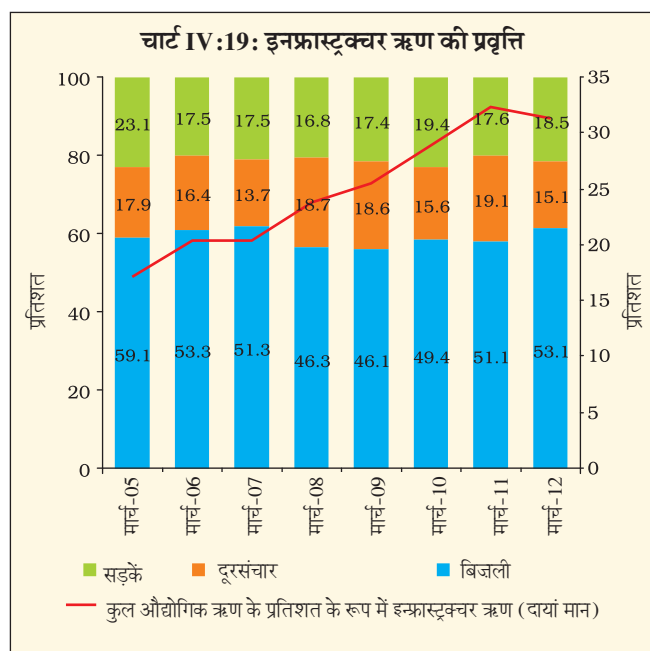
असंतुलन की स्थिति बन सकती है। इसका विस्तृत विश्लेषण बॉक्स IV.2 में दिया गया है।

**प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण**

4.47 2011-12 के दौरान, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त अग्रिम समायोजित निवल बैंक ऋण/तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, के 40 प्रतिशत से कम थे। इसके अलावा, कृषि और दुर्बल घटकों को सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त अग्रिम समग्र स्तर पर क्रमशः 18 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से कम थे (सारणी IV.21)।

**देशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाना चिंता का विषय बना हुआ है**

4.48 मार्च 2012 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी बैंक-वार अनंतिम आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकारी क्षेत्र के 26 में से 16 बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी 40 प्रतिशत का समग्र लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए थे। कृषि



**बॉक्स IV.2: बैंकों से बुनियादी सुविधाओं के लिए उधार और आस्ति-देयता असंतुलन: लिंकेज कितना मजबूत है?**

भारत जैसे विकासशील देश में, देश की वृद्धि-गति को बनाए रखने में बुनियादी सुविधाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर के अनुसार, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बुनियादी सुविधा क्षेत्र के लिए अपेक्षित निवेश 45 ट्रिलियन रुपये होगा। इसका अर्थ यह है कि जीडीपी-बुनियादी सुविधा निवेश को 2011-12 के 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 2016-17 तक 10 प्रतिशत करना होगा। किंतु बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी निवेश का देश के वित्तीय क्षेत्र के लिए विशेष महत्व होता है क्योंकि ये निवेश विशेष रूप से एकमुश्त हते हैं और इनमें निवेश के बाद परिणाम प्राप्त होने की अवधि बहुत लंबी होती है और इस प्रकार आस्ति देयता असंतुलन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, बुनियादी सुविधा परियोजनाएं अनेक बार क्रियाविधिक विलंब से प्रभावित होती हैं जिससे उधारदाता को समय पर प्रतिलाभ न मिलने का जोखिम बना रहता है।

पिछले कुछ वर्षों में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बुनियादी सुविधा घटक को दिए गए ऋण में 40-43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में, कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण में बुनियादी सुविधा घटक का हिस्सा लगभग 15 प्रतिशत था। इसके विपरीत पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की अल्पावधि देयताओं में वृद्धि हुई है। आस्ति-देयता असंतुलन, जो कि अल्पकालिक जमाराशि और उधार (एक वर्ष तक की अवधिपूर्णता) के अनुपात और अल्पकालिक ऋण और निवेश (एक वर्ष तक की अवधिपूर्णता) के अनुपात के बीच अंतर से नापा गया था, में भी हाल के वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखी (चार्ट 2.1)।

बैंकिंग क्षेत्र के आस्ति देयता असंतुलन पर बुनियादी सुविधा उधार के संभाव्य प्रभाव को समझने के लिए एक प्रतिगमन विश्लेषण किया गया जिसमें आस्ति देयता प्रबंधन को स्वतंत्र चर के रूप में और बुनियादी सुविधा क्षेत्र को दिए

**सारणी: प्रतिगमन विश्लेषण के परिणाम**

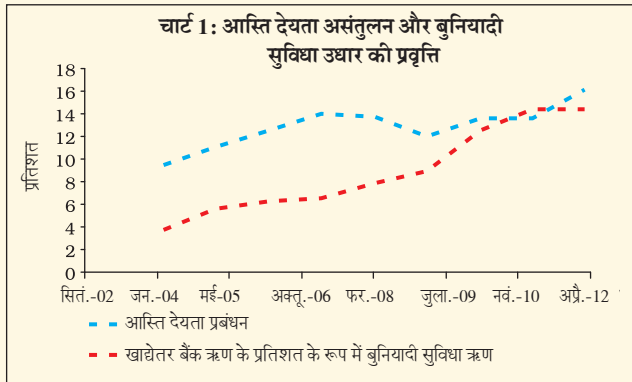
निर्भर चर: आस्ति-देयता प्रबंधन			
नमूना अवधि: 2004-012			
	सहगुणांक	मानक चूक	टी-स्टैट
अवरोध	30.43	17.27	1.76*
सावधि जमाराशि का अनुपात	-0.31	0.27	-1.14*
बुनियादी सुविधा ऋण का अनुपात	0.38	0.12	3.17**
आर स्क्वेयर	0.68	डरबिन-वाटसन स्टेटिस्टिक: 2.3	
समायोजित आर स्क्वेयर	0.58		

**टिप्पणी:** 1. \*: महत्वपूर्ण नहीं  
2. \*\*: 1 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण

गए ऋण को कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में और कुल जमाराशि में सावधि ऋण के अनुपात को स्पष्टीकरणात्मक चर के रूप में माना गया। जहां सावधि जमाराशि में बढ़े हुए अनुपात से तुलनपत्र की स्थिरता में वृद्धि होना और इस प्रकार आस्ति-देयता असंतुलन में कमी आना अपेक्षित है, वहीं बुनियादी सुविधा उधार में वृद्धि से आस्ति-देयता असंतुलन में और वृद्धि होने की संभावना है। विश्लेषण के प्रायोगिक परिणामों को सारणी 2.1 में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परिणामों से यह देखा जा सकता है कि कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण में बुनियादी सुविधा ऋण का अनुपात आस्ति-देयता असंतुलन से सकारात्मक रूप से सहसंबंधित है और यह सहसंबंध सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किंतु सावधि जमाराशि अनुपात से संबंधित सहसंबंध नकारात्मक होने के बावजूद, संबंधित 'टी' मूल्य सांख्यिकीय दृष्टि से अत्यल्प है।

बैंकों द्वारा बुनियादी सुविधा के वित्तीयन के संभाव्य प्रतिकूल प्रभावों को पहचानते हुए रिजर्व बैंक ने हाल के वर्षों में कुछ उपाय किए हैं जिनमें बैंकों को आईडीएफसी/अन्य विदेशी संस्थाओं के साथ टेक आउट वित्तपोषण व्यवस्था में शामिल होने की अनुमति देना शामिल है। इसके अलावा, इस बात की आवश्यकता है कि बैंकों के आस्ति-देयता असंतुलन पर बुनियादी सुविधा उधार के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया जाए। इस बात की भी आवश्यकता है कि बुनियादी सुविधा की परियोजनाओं को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाया जाए और साथ ही कारपोरेट बांड बाजार को मजबूत किया जाए जिससे बुनियादी सुविधा निधि के लिए बैंकों पर निर्भरता में कमी आयेगी।



और दुर्बल घटकों संबंधी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उप-लक्ष्य पूरे न करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या क्रमशः 15 और 11 थी। मार्च 2012 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को, निजी क्षेत्र के 6 बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी 40 प्रतिशत का समग्र लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए थे। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के 13 बैंक कृषि संबंधी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उप-लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए

(चार्ट IV.20)। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी ऋण का विस्तृत विश्लेषण बॉक्स IV.3 में दिया गया है।

**बैंकों का खुदरा ऋण संविभाग उच्च दर पर बढ़ा**

4.49 2011-12 के दौरान, बैंकों के खुदरा ऋण संविभाग में पिछले वर्ष की तुलना में उच्च दर पर वृद्धि हुई जिसमें क्रेडिट

**सारणी IV.21: बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार**  
(मार्च 2012 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को)

(राशि ₹ बिलियन में)

मंद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक***	
	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत*	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत*	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7
<b>प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिम जिसमें से</b>	<b>11,307</b>	<b>37.2</b>	<b>2,864</b>	<b>39.4</b>	<b>805</b>	<b>40.9</b>
कृषि**	4,786	15.8	1,042	14.3	1	0.1
कमजोर वर्ग	2,888	9.5	389	5.4	-	-
लघु उद्यम	3,966	13.1	1,105	15.2	217	11

**टिप्पणी:** 1. \*: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा ऑफ बेलेंस शीट एक्सपोजर (ओबीई) की राशि के समतुल्य ऋण, पिछले वर्ष के 31 मार्च को जो भी अधिक हो, का 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।  
2. \*\*: कृषि के लिए एएनबीसी/ओबीई का 18 प्रतिशत लक्ष्य, पिछले वर्ष के मार्च की समाप्ति तक, जो भी अधिक हो।  
3. \*\*\*: विदेशी बैंकों के लिए एएनबीसी/ओबीई का 32 प्रतिशत लक्ष्य तय किया है पिछले वर्ष के मार्च की समाप्ति तक जो भी अधिक हो।  
4. 'एएनबीसी/ओबीई के प्रतिशत' के रूप में दर्शाये गये आंकड़े एएनबीसी/ओबीई के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की राशि होते हैं, जो पिछले वर्ष मार्च की समाप्ति पर अधिक है।  
5. - कुछ नहीं/नगण्य।  
6. आंकड़े अंतिम हैं।

कार्ड संबंधी प्राप्तियां और अन्य निजी ऋण मुख्य थे। बैंकों के खुदरा ऋण संविभाग में आवास ऋण का हिस्सा आधे से अधिक बना रहा (सारणी IV.22)।

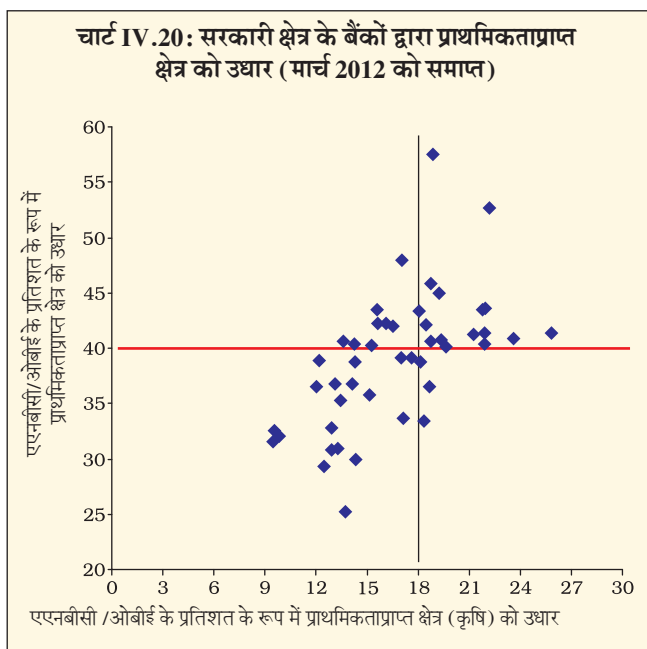
**संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण में कम वृद्धि हुई**

4.50 रिजर्व बैंक पूंजी बाजार, स्थावर संपदा और पण्य को संवेदनशील क्षेत्र मानता है क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अचानक

काफी ऋण मिल जाए तो बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिसका कारण संबंधित आस्ति/उत्पाद बाजारों में मूल्यों में घट-बढ़ होना है। पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में संवेदनशील क्षेत्रों को प्राप्त ऋण में कमी आयी। इसके परिणामस्वरूप, कुल ऋण में संवेदनशील क्षेत्रों को प्राप्त ऋण के अनुपात में भी कमी आयी। संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति कुल बैंक एक्सपोजर में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा स्थावर संपदा क्षेत्र का था। बैंक समूह स्तर पर, इन क्षेत्रों के प्रति विदेशी बैंकों का एक्सपोजर अन्य बैंक समूहों की तुलना में अधिक था (परिशिष्ट सारणी IV.3)।

**6. पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन सरकारी और प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों में कमी आयी**

4.51 उदार होते जा रहे और प्रतिस्पर्धी बाजार में पूंजी बाजार के माध्यम से बैंकों द्वारा संसाधन जुटाना उनके तुलनपत्र में वृद्धि का महत्वपूर्ण मार्ग है। किंतु देशी बाजार की विद्यमान अनिश्चितता और 2011-12 की पहली छमाही के दौरान इक्विटी बाजार के तुलनात्मक रूप से मंद निष्पादन के कारण 2011-12 के दौरान बैंक सरकारी निर्गमों के माध्यम से संसाधन जुटाने से दूर रहे (सारणी IV.23)।



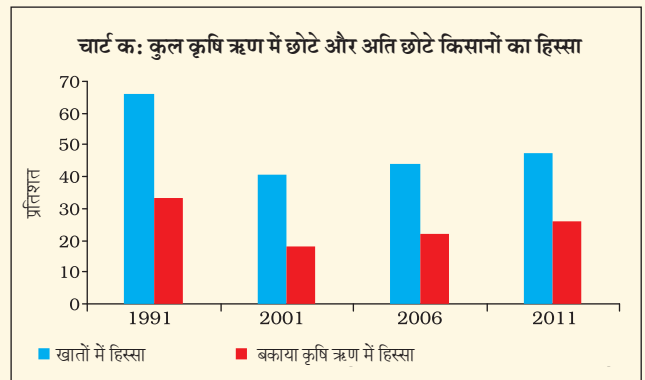
### बॉक्स IV.3: प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण - क्या बड़े ऋणों की आवश्यकता के प्रति झुकाव है?

प्रमुख प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों अर्थात् कृषि और लघु उद्योगों को औपचारिक ऋण देने के प्रयास 1968 में ही प्रारंभ किए गए थे जब रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय ऋण परिषद के साथ विचार-विमर्श करके पहली बार इस बात पर बल दिया था कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार के प्रति वाणिज्य बैंकों की प्रतिबद्धता बढ़ायी जानी चाहिए। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के वर्णन को 1972 में औपचारिक रूप दिया गया जिसका आधार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम संबंधी सांख्यिकी पर अनौपचारिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट थी। प्रारंभिक वर्षों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों का कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था किंतु बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने कुल अग्रिमों में इन क्षेत्रों के हिस्से को मार्च 1979 तक 33 प्रतिशत के स्तर तक ले जाएं। बाद में, बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों के अपने अनुपात को मार्च 1985 तक 40 प्रतिशत के स्तर तक ले जाएं।

बाद में, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों पर अन्य समितियों और कार्यदलों ने बैंकों के लिए किसी विशिष्ट प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों के दायित्व के संबंध में सिफारिशें देना जारी रखा, हालांकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों की परिभाषा में समय-समय पर आवधिक परिवर्तन हुआ है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों के संबंध में हाल की घटना में रिजर्व बैंक में श्री एम.वी.नायर की अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया जाना शामिल है जिसका दायित्व प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों के वर्तमान श्रेणीकरण की पुनः जांच करना और संशोधित दिशानिर्देशों का सुझाव देना है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के वर्तमान मानदंडों के अनुसार, 20 से अधिक शाखाओं वाले देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और विदेशी बैंकों को पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उनके संबंधित समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 40 प्रतिशत और 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को 32 प्रतिशत या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को देना है। इस संदर्भ में, इस बात को समझने का प्रयास किया गया है कि क्या प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की परिभाषा के विस्तार से उधार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत छोटे उधारकर्ताओं की कीमत पर बड़े खातों में तो केंद्रित नहीं हो गए।

अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है जिससे इस क्षेत्र की ओर पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एएनबीसी के 18 प्रतिशत का उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया। जहां इस बात की चिंता रही है कि सामान्यतः बैंक इस लक्ष्य का अनुपालन नहीं करते हैं, वहीं अलग-अलग रूप में किया गया विश्लेषण दर्शाता है कि कुल कृषि ऋण का एक-चौथाई भाग ही अति छोटे किसानों को मिलता है। इसके अलावा, कुल कृषि खातों में छोटे और अति छोटे किसानों का हिस्सा पिछले दो दशकों में निरंतर कम होता गया है। किंतु सकारात्मक पक्ष में, कुल बकाया कृषि ऋण में छोटे और अति छोटे किसानों के हिस्से में 2000 के दशक में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखी है (चार्ट क)। महत्वपूर्ण रूप से, मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, कुल कृषि ऋण का 13.6 प्रतिशत कंपनियों, साझेदारी फर्मों और कृषि कार्य करने वाली संस्थाओं को मिला था।



इसी अवधि में कुल कृषि ऋण का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों से संबंधित था।

माइक्रो और छोटे उद्यमों को प्राप्त ऋण के आंकड़ों से भी तुलनात्मक रूप से बड़े उद्यमों के पक्ष में झुकाव का पता चलता है। मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, माइक्रो और छोटे उद्यमों के प्रति कुल बकाया ऋण में से 5 लाख रुपये तक के निवेश वाले माइक्रो (विनिर्माण) और 2 लाख रुपये तक के निवेश वाले माइक्रो (सेवा) उद्यमों को मात्र 21.1 प्रतिशत ऋण प्राप्त हुआ था जबकि इनका निर्धारित लक्ष्य 40 प्रतिशत है।

विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों को दुर्बल क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस श्रेणी के लिए एएनबीसी के 10 प्रतिशत का अलग लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। दुर्बल क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के खातों की संख्या में 2000 के दशक के प्रारंभ की तुलना में बाद की अवधि में उच्च वृद्धि होने के बावजूद, छोटे और अति छोटे किसानों संबंधी बकाया राशि में डीआरआई लाभार्थियों और एसएचजी में 2000 के दशक के अंतिम समय में गिरावट हुई (सारणी 3.1)।

इस प्रकार, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत और विशेष रूप से कृषि और माइक्रो तथा छोटे उद्यमों के अंतर्गत, अधिकतर ऋण तुलनात्मक रूप से बड़े खातों में संकेद्रित हुआ है। समावेशी वृद्धि की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋण संकेद्रन में परिवर्तन की आवश्यकता है।

**सारणी 3.1: एसबीबी के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार (मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को)**

श्रेणी	खातों की संख्या		बकाया राशि	
	2001 की तुलना में 2006	2006 की तुलना में 2011	2001 की तुलना में 2006	2006 की तुलना में 2011
कमजोर वर्ग	3.4	9.8	24.9	26.7
छोटे और अति छोटे किसान	7.9	9.9	31.7	25.8
डीआरआई लाभार्थी	-9.7	12.2	11.6	7.1
एसएचजी को अग्रिम	72.9	19.0	99.7	35.6

**स्रोत:** बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को प्रस्तुत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की विवरणियां।

### सारणी IV.22: बैंकों का खुदरा पोर्टफोलियो

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में बकाया		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1	3,607	4,118	15.1	14.2
2	46	27	50.3	-40.9
3	187	223	-13.5	19.6
4	1,002	1,162	27.8	16.0
5	2,469	3,069	18.5	24.3
<b>कुल खुदरा ऋण (1 से 5)</b>	<b>7,310</b>	<b>8,599</b>	<b>17.0</b>	<b>17.6</b>
	(18.3)	(18.4)		

**टिप्पणी:** 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल उधारों और अग्रिम में खुदरा उधारों के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।  
2. कुल उधारों और अग्रिमों की राशि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऑफसाइट विवरणियों (देशी) में दिए अनुसार हैं।  
3. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकता है।  
4. बिलियन की संख्याओं के पूर्णांकन के कारण घटकों में अंतर हो सकता है।

**स्रोत:** ऑफसाइट विवरणियों (देशी) पर आधारित।

4.52 बैंकों द्वारा 2011-12 के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाये गये संसाधन भी पिछले वर्ष की तुलना में कम थे। प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से संसाधन जुटाने में कमी आने का मामला सरकारी क्षेत्र के बैंकों का था जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से संसाधन जुटाना जारी रखा। यूरोपीय सरकारी ऋण संकट बढ़ते जाने से उभरी वैश्विक अनिश्चितता के कारण भारतीय बैंकों ने यूरो निर्गमों से संसाधन नहीं जुटाए (सारणी IV.24)।

### बीएसई बैंकेक्स का निष्पादन मंद था

4.53 भारतीय इक्विटी बाजार में दिसंबर 2011 तक नरमी देखी गयी जिसके बाद नए संस्थागत निवेशक क्रय के कारण 2011-12 की चौथी तिमाही में तेजी आयी। इसी के अनुरूप, बीएसई बैंकेक्स, जो कि बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों का प्रतिनिधि है, में

### सारणी IV.23: बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम

(राशि ₹ बिलियन में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल	
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7
2010-11	43.3	-	9.2	-	52.5	-
2011-12	-	-	-	-	-	-

**टिप्पणी:** शून्य / नगण्य

**स्रोत:** सेबी

### सारणी IV.24: प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ बिलियन में)

श्रेणी	2010-11		2011-12	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र के बैंक	5	61	10	62
सरकारी क्षेत्र के बैंक	25	209	9	44
<b>कुल</b>	<b>30</b>	<b>270</b>	<b>19</b>	<b>106</b>

**टिप्पणी:-** 2011-12 के लिए डेटा अर्न्तम है।

**स्रोत:-** मर्चेन्ट बैंकर्स और वित्तीय संस्थान

2011-12 में नकारात्मक प्रतिलाभ दर्ज हुआ। बीएसई बैंकेक्स में घट-बढ़ भी बीएसई सेंसेक्स की तुलना में अधिक थी जो कि बैंकिंग शेयरों के प्रति अधिक जोखिम की धारणा दर्शाती है। किंतु बीएसई बैंकेक्स के निष्पादन में वर्ष में बाद में सुधार हुआ। फरवरी-मार्च 2012 के दौरान यह बीएसई सेंसेक्स से आगे निकल गया (सारणी IV.25 और चार्ट IV.21)।

4.54 बीएसई बैंकेक्स की समग्र प्रवृत्ति के समरूप अधिकतर बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में कम मूल्य-आय (पी/ई) अनुपात दर्ज किया। 2011-12 में कुल पण्यवर्त में बैंक शेयरों का हिस्सा बढ़ती प्रवृत्ति का होने के बावजूद कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक शेयरों का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया (परिशिष्ट सारणी IV.4 सारणी IV.25)।

### सारणी IV.25: बैंक स्टॉक्स का जोखिम-प्रतिफल निष्पादन, टर्नओवर और पूंजीकरण

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13#
1	2	3	4	5
<b>1. प्रतिफल*</b>				
बीएसई बैंकेक्स	137.2	24.9	-11.6	11.8
बीएसई सेंसेक्स	80.5	10.9	-10.5	7.8
<b>2. उतार-चढ़ाव@</b>				
बीएसई बैंकेक्स	16.5	10.3	9.7	4.8
बीएसई सेंसेक्स	11.9	6.3	6.2	3.8
<b>3. कुल कारोबार में बैंक स्टॉक्स के कारोबार का हिस्सा</b>	<b>8.3</b>	<b>9.5</b>	<b>11.4</b>	<b>14.4</b>
<b>4. कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टॉक्स के पूंजीकरण का हिस्सा**</b>	<b>10.0</b>	<b>11.9</b>	<b>11.5</b>	<b>12.0</b>

**टिप्पणी:** 1.\* : अंक-दर-अंक आधार पर सूचकांक में प्रतिशत घटबढ़।

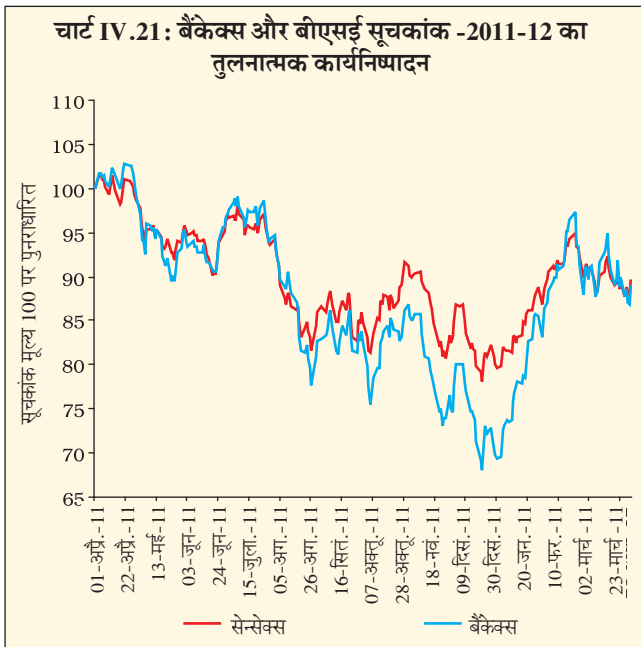
2.@ : घटबढ़ के सह गुणांक के रूप में परिभाषित।

3.\*\* : अवधि के अंत में

4.# : अप्रैल - सितम्बर 28, 2012.

**स्रोत:** बीएसई.

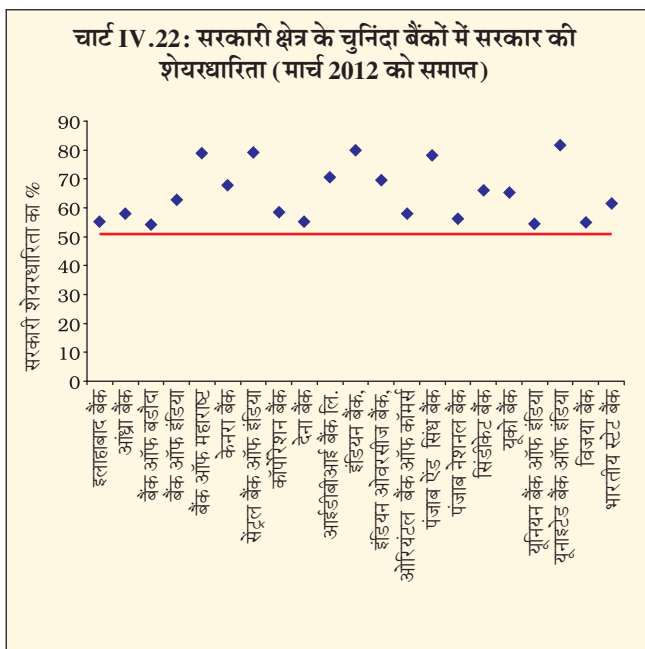




## 7. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में शेयरधारिता पद्धति

### सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी शेयरधारिता सांविधिक अपेक्षा से पर्याप्त अधिक थी

4.55 2011-12 में सरकारी क्षेत्र के अधिकतर बैंकों में सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से अधिक थी हालांकि सरकारी क्षेत्र के अनेक बैंकों में यह शेयरधारिता उक्त निर्धारण के समीप थी (चार्ट IV.22)। मार्च 2012 के



## सारणी IV.26: निजी शेयरधारिता के प्रतिशत के आधार पर वर्गीकृत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या \* (मार्च 2012 के अंत में)

शेयर धारिता की श्रेणी	निजी निवासी शेयर धारिता	निजी अनिवासी शेयर धारिता	कुल निजी शेयर धारिता
1	2	3	4
10 प्रतिशत तक	-	17	-
10 से अधिक और 20 प्रतिशत तक	5	9	2
20 से अधिक और 30 प्रतिशत तक	8	-	4
30 से अधिक और 40 प्रतिशत तक	8	-	6
40 से अधिक और 43 प्रतिशत तक	5	-	14

**टिप्पणी:** --: शून्य /नगण्य  
\* 19 राष्ट्रीयकृत बैंको, भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सहित।

अंत में, सरकारी क्षेत्र के 26 बैंकों में से 10 में सरकार की 20 से 40 प्रतिशत तक की शेयरधारिता थी। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी शेयरधारिता मात्र 17.4 प्रतिशत तक थी। मार्च 2012 के अंत में, निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी शेयरधारिता 70.7 प्रतिशत तक की थी जो कि 74 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर थी (सारणी IV.26 और परिशिष्ट सारणी IV.5)।

## 8. विदेशी बैंकों के भारत में परिचालन और भारतीय बैंकों के विदेश में परिचालन

4.56 मार्च 2012 के अंत में, भारत में 41 विदेशी बैंक कार्यरत थे जिनकी 323 शाखाएं थीं। अन्य 46 विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालय भारत में थे। भारत में विदेशी बैंकों में से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की शाखाएं सर्वाधिक (96 शाखाएं) थीं जिसके बाद एचएसबीसी (50 शाखाएं), सिटी बैंक (42 शाखाएं) और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन.वी. (31 शाखाएं) का स्थान था।

4.57 मार्च 2012 के अंत में, विदेश में 23 भारतीय बैंकों की 250 शाखाएं थीं जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 244 थी। इन विदेशी शाखाओं में से 215 शाखाएं सरकारी क्षेत्र के बैंकों की थीं। इन बैंकों में, स्टेट बैंक की शाखाएं सर्वाधिक थीं जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ोदा और बैंक ऑफ इंडिया का स्थान था। इसके

**सारणी IV.27: भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन**  
(मार्च के अंत में)

बैंक का नाम	शाखा		सहायक संस्था		प्रतिनिधि कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		कुल	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 इलाहाबाद बैंक	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2
2 आंध्र बैंक	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
3 बैंक ऑफ बड़ौदा	47	47	9	9	3	2	1	1	60	59
4 बैंक ऑफ इंडिया	24	24	3	4	5	5	1	0	33	33
5 केनरा बैंक	4	5	0	0	1	1	0	0	5	6
6 कॉर्पोरेशन बैंक	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
7 इंडियन बैंक	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4
8 इंडियन ओवरसीज बैंक	6	6	1	0	4	3	0	0	11	9
9 आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
10 पंजाब नेशनल बैंक	4	4	3	3	4	5	1	1	12	13
11 भारतीय स्टेट बैंक	45	52	5	5	8	8	4	4	62	69
12 स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
13 सिंडिकेट बैंक	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
14 यूको बैंक	4	4	0	0	2	1	0	0	6	5
15 यूनियन बैंक	1	1	0	0	5	5	0	0	6	6
16 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
17 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
18 ऐक्सिस बैंक	3	4	0	0	3	3	0	0	6	7
19 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	2	2	0	0	2	2	0	0	4	4
20 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	8	9	3	3	8	8	0	0	19	20
21 इंडसइंड बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
22 फेडरल बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
23 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
कुल	155	165	24	24	56	55	7	6	242	250

अलावा, विदेश में 25 भारतीय बैंकों के 55 प्रतिनिधि कार्यालय थे। विदेश में भारतीय बैंकों के अनुषंगी कार्यालयों और संयुक्त उद्यमों की संख्या क्रमशः 24 और 6 थी (सारणी IV.27)।

## 9. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

4.58 रिजर्व बैंक वर्षों से बैंकों के दैनिक कार्यों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर बल देता आया है। प्रौद्योगिकी और बैंकिंग सेवाओं में बढ़ते कौशल से रिजर्व बैंक द्वारा बल दिए गए वित्तीय समावेशन की निरंतर प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। हाल के वर्षों में विभिन्न स्थानों में ऑफ साइट एटीएम की संख्या बढ़ने और बैंकिंग सेवाएं देने में मोबाइल फोन की भूमिका बढ़ने से दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने में सुविधा हुई है। रिजर्व बैंक के आईटी विज्ञान दस्तावेज, 2011-17 में बैंकिंग

में प्रमुख आईटी अप्लिकेशन्स लागू करने की योजना दी गयी है जिसमें कारोबार निरंतरता प्रबंधन, सूचना सुरक्षा नीति और कारोबार प्रक्रिया की पुनर्संरचना के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने में निरंतरता पर विशेष बल दिया गया है।

4.59 बैंकों में कंप्यूटरीकरण और कोर बैंकिंग समाधान लागू करने का कार्य लगभग पूरा होने को आने से, अब बैंकिंग में अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने पर फोकस अंतरित किया गया है जिसमें उनके ग्राहक संबंध प्रबंधन में विस्तार करने और प्रबंध सूचना प्रणाली सहित आंतरिक प्रभावशीलता में सुधार लाने और सूचना प्रौद्योगिकी लागू करने से उभरने वाले जोखिमों के प्रबंधन के लिए विश्लेषण प्रक्रिया और कारोबारी आसूचना का प्रयोग किया जाता है।

### एटीएम की संख्या में निरंतर वृद्धि से डोर-स्टेप बैंकिंग में प्रगति का संकेत मिलता है

4.60 2011-12 के दौरान बैंकों ने 21,000 अतिरिक्त एटीएम लगाए। मार्च 2012 के अंत में कुल एटीएम में से 60 प्रतिशत से अधिक एटीएम सरकारी क्षेत्र के बैंकों के थे जबकि लगभग एक-तिहाई निजी क्षेत्र के नए बैंकों के थे (सारणी IV.28)।

### सरकारी क्षेत्र के बैंक डेबिट कार्डों के प्रमुख जारीकर्ता थे

4.61 क्रेडिट कार्डों के निर्गम में गिरावट आयी जबकि डेबिट कार्डों में अधिक तेजी की प्रवृत्ति देखी गयी। विदेशी बैंकों ने डेबिट कार्डों के संबंध में भी गिरावट दर्शाई। मार्च 2012 के अंत में, कुल डेबिट कार्डों में से तीन-चौथाई से अधिक सरकारी क्षेत्र

**सारणी IV.28: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम (मार्च 2012 के अंत में)**

क्रम सं.	बैंक समूह	ऑन-साइट एटीएम	ऑफ साइट एटीएम	एटीएम की कुल संख्या
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>सरकारी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>34,012</b>	<b>24,181</b>	<b>58,193</b>
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक*	18,277	12,773	31,050
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	15,735	11,408	27,143
<b>2.</b>	<b>निजी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>13,249</b>	<b>22,830</b>	<b>36,079</b>
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	3,342	2,429	5,771
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	9,907	20,401	30,308
<b>3.</b>	<b>विदेशी बैंक</b>	<b>284</b>	<b>1,130</b>	<b>1,414</b>
<b>सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (1+2+3)</b>		<b>47,545</b>	<b>48,141</b>	<b>95,686</b>

टिप्पणी: \* आईडीबीआई बैंक लि.को छोड़कर

**सारणी IV.29: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड (मार्च के अंत में)**

(मिलियन में)

क्र. सं.	बैंक समूह	बकाया क्रेडिट कार्डों की संख्या		बकाया डेबिट कार्डों की संख्या	
		2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>सरकारी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>3.08</b>	<b>3.06</b>	<b>170</b>	<b>215</b>
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक	0.78	0.84	80	103
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	2.30	2.22	90	112
<b>2.</b>	<b>निजी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>9.32</b>	<b>9.67</b>	<b>53</b>	<b>60</b>
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	0.04	0.04	12	14
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	9.28	9.63	41	46
<b>3.</b>	<b>विदेशी बैंक</b>	<b>5.64</b>	<b>4.92</b>	<b>3.9</b>	<b>3.8</b>
<b>सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (1+2+3)</b>		<b>18.04</b>	<b>17.65</b>	<b>228</b>	<b>278</b>

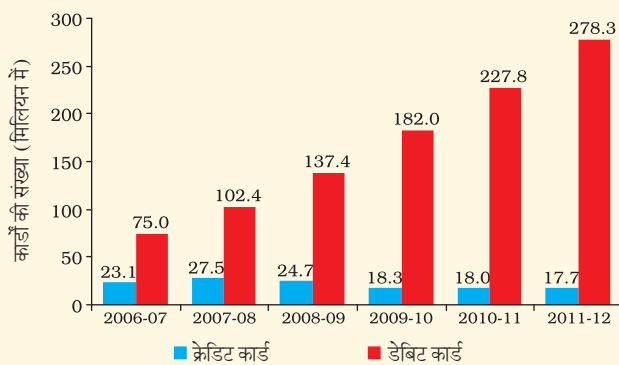
नोट: बिलियन की संख्याओं के पूर्णांकन के कारण घटकों में अंतर हो सकता है।

के बैंकों द्वारा जारी किए गए थे। इसके विपरीत, मार्च 2012 को बकाया क्रेडिट कार्डों में से आधे से अधिक निजी क्षेत्र के नए बैंकों के थे (सारणी IV.29 और चार्ट IV.23)।

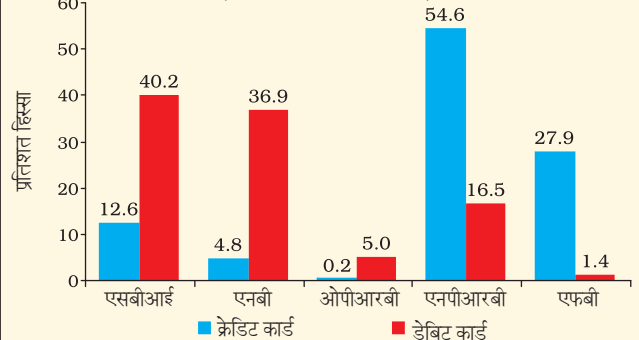
### प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से हुए लेनदेनों की मात्रा और मूल्य - दोनों में वृद्धि हुई

4.62 हाल के वर्षों में नकदी रहित भुगतान की प्रवृत्ति बढ़ी है जिसमें प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से हुए लेनदेनों की मात्रा और मूल्य - दोनों में वृद्धि हुई (सारणी IV.30 और बॉक्स IV.4)।

**चार्ट IV.23 क: बकाया क्रेडिट/डेबिट कार्डों की संख्या**



**चार्ट IV.23 ख: कुल क्रेडिट/डेबिट कार्डों में बैंक समूहों का हिस्सा (मार्च 2012 को समाप्त)**



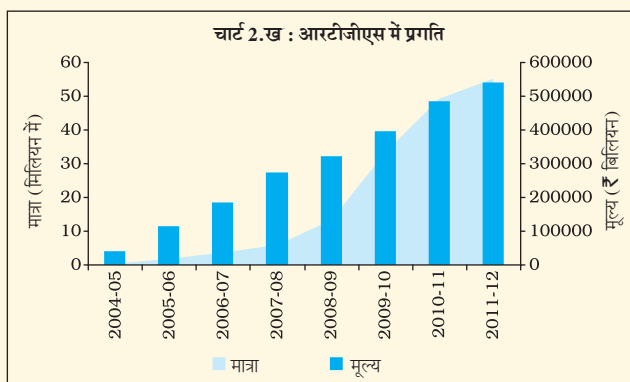
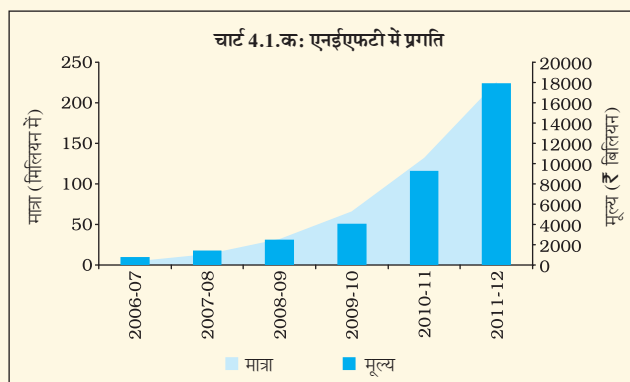
### बॉक्स IV.4: भुगतान प्रणाली में परिवर्तन की प्रवृत्ति: नकदी से नकदी रहित

भारत में, भुगतान का प्रमुख साधन नकदी ही रहा है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संचलन की मुद्रा में कमी आने की प्रवृत्ति दिख रही है। रिजर्व बैंक की नीतिगत पहलें और विनियामक रूढ़ान सुरक्षित और कार्यकुशल नकदी रहित भुगतान प्रणाली की स्वीकार्यता और उसका उपयोग बढ़ाने के रहे हैं जिसमें चेक, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और ईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से लेनदेन शामिल हैं। इन उपायों के कारण जीडीपी-नकदी रहित खुदरा भुगतान अनुपात पिछले तीन वर्षों से 6 प्रतिशत के आसपास रहा है (सारणी 4.1)।

बैंकों की अगुवाई में मोबाइल बैंकिंग की लोकप्रियता हाल के वर्षों में बढ़ी है। जून 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार, 69 बैंकों को मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदन दिया गया था जिनमें से 49 से अपने परिचालन प्रारंभ कर दिए हैं। इसके अलावा, नवंबर 2010 में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आइएमपीएस) शुरू करने का अनुमोदन दिया गया जो कि अनूठी 24x7 इंटर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली है जिसके अंतर्गत लाभार्थी को तत्काल क्रेडिट मिल जाता है। यह माध्यम अब स्थापित हो जाने और ग्राहकों की अधिक स्वीकृति प्राप्त होने के कारण रिजर्व बैंक ने मोबाइल बैंकिंग की पूर्ववर्ती लेनदेन सीमा हटा दी है। अब बैंक अपने अपने जोखिम धारणा के आधार पर अपने बोर्डों के अनुमोदन से प्रति लेनदेन सीमा तय कर सकते हैं।

इसके अलावा, देश की दो प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों अर्थात् आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से होने वाले लेनदेन की मात्रा और मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है (चार्ट 4.1क और 4.1ख)।

प्रीपेड भुगतान लिखत नकदी लेनदेन के सुविधाजनक स्थानापन्न के रूप में उभरे हैं और साथ ही ये लेखापरीक्षा को भी सुगम बनाते हैं। प्रीपेड भुगतान लिखत ऐसे लिखत हैं जो उनमें जमा किए गए मूल्य से सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं। जून 2012 के अंत में, 40 बैंकों (डाक विभाग, भारत सरकार सहित) और 21 गैर-बैंक संस्थाओं को प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली (पीपीआई) अधिनियम, 2007 के तहत भारत में अनुमोदन/प्राधिकार दिया गया था। 2011-12 के दौरान, 587.50 मिलियन पीपीआई जारी किए गए थे और इन पीपीआई में जमा मूल्य 26.54 बिलियन रुपये था। तीन प्रकार के पीपीआई जारी करना लोकप्रिय है, अर्थात् पेपर वाउचर, कार्ड और एम-वॉलेट। इनमें से, पेपर वाउचर संख्या और मूल्य



की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय है। इन्हें मुख्यतः गैर-बैंक संस्थाओं ने जारी किया था (सारणी 4.2)। किंतु इन पेपर आधारित पीपीआई को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरित करने के प्रयास जारी हैं।

इसके अलावा, अक्टूबर 2011 में लागू किए गए देशी मुद्रा अंतरण दिशानिर्देशों में दी गयी शिथिलता से एम-वॉलेट के प्रयोग सहित इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड भुगतान लिखतों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को और बल मिलेगा जिसमें सभी प्राधिकृत संस्थाओं (बैंक और गैर-बैंक- दोनों) को समर्थ बनाया जाएगा कि वे औपचारिक भुगतान चैनलों के माध्यम से देशी प्रेषण में वृद्धि करें।

#### सारणी 4.1: भुगतान प्रणाली की प्रवृत्ति

(₹ बिलियन)

वर्ष	नकदी रहित खुदरा भुगतान*	जीडीपी-नकदी रहित खुदरा भुगतान अनुपात	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संचलन में मुद्रा
2006-07	1,94,459	4.53	11.77
2007-08	3,05,382	6.12	11.85
2008-09	3,29,736	5.91	12.38
2009-10	4,06,116	6.29	12.38
2010-11	4,76,291	6.21	12.36
2011-12	5,16,332	5.83	12.04

\* चेक, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस ग्राहक लेनदेन

स्रोत: विभिन्न भारिबैं प्रकाशन और भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस

#### सारणी 4.2: प्रीपेड भुगतान लिखतों का विस्तार

(मार्च 2012 के अंत में)

(मात्रा मिलियन में और मूल्य ₹ बिलियन में)

प्रीपेड भुगतान लिखत का प्रकार	जारी किए गए		जारी किए गए	
	पीपीआई की संख्या	पीपीआई में प्रतिशत	पीपीआई का मूल्य	पीपीआई में प्रतिशत
पेपर वाउचर	42.00	97.0	1.76	60.8
कार्ड आधारित	0.57	1.3	1.04	35.8
मोबाइल अकाउंट/वॉलेट	0.55	1.3	0.1	3.5
<b>कुल</b>	<b>43.00</b>	<b>100.0</b>	<b>2.9</b>	<b>100.0</b>

नोट: बिलियन की संख्याओं के पूर्णांकन के कारण घटकों में अंतर हो सकता है।

**सारणी IV. 30: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की मात्रा और मूल्य**

(मात्रा मिलियन में, मूल्य ₹ बिलियन में)

वर्ष	मात्रा		प्रतिशत घट-बढ़		मूल्य		प्रतिशत घटबढ़	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईसीएस क्रेडिट	117	122	19.5	3.6	1,817	1,838	54.5	1.2
ईसीएस डेबिट	157	165	5.0	5.1	736	834	5.9	13.3
क्रेडिट कार्ड	265	320	13.2	20.7	755	966	22.2	27.9
डेबिट कार्ड	237	328	39.3	38.2	387	534	46.6	38.0
एनईएफटी	132	226	99.5	70.9	9,321	17,903	127.6	92.1
आरटीजीएस	49	55.0	48.5	11.6	4,84,872	5,39,307	22.9	11.2

**टिप्पणी:** आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

**कारोबार निरंतरता योजना और स्वचालित आंकड़ा प्रवाह लागू करने में प्रगति हुई है**

4.63 वर्तमान स्थिति में, भारत में बैंकिंग मुख्यतः प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। अतः यह आवश्यक है कि बैंकों के पास आपदा से राहत पाने और कारोबार की निरंतरता बनाए रखने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नैसर्गिक आपदा या परिचालनगत विफलता का मुकाबला किया जा सके। हाल के वर्षों में, रिजर्व बैंक की सहायता से समन्वित कारोबार निरंतरता प्रबंधन व्यवस्था विकसित की गयी है जिसमें डेटा केंद्रों सहित सभी कारोबारी कार्यों के लिए निरंतरता की योजना शामिल है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी की विफलता से पैदा होने वाली कारोबारी प्रक्रिया में व्यवधान आने के मामले के समाधान के लिए भारिबैं डेटा केंद्रों में उपयुक्त आपदा-राहत और कारोबार निरंतरता व्यवस्था लागू की गयी है।

4.64 विनियामक रिपोर्टिंग में सटीकता और कार्य समय पर होने के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य बैंकों से रिजर्व बैंक को कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) या अन्य आईटी प्रणालियों के माध्यम से स्वचालित आंकड़ा प्रवाह की परियोजना 2010-11 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित की गयी। एक कोर समूह, जिसमें बैंकों, रिजर्व बैंक, आईडीआरबीटी और आईबीए के प्रतिनिधि शामिल थे, द्वारा तैयार किया गया एप्रोच पेपर नवंबर 2011 में जारी किया गया जिसमें इसे दो चरणों में लागू करने का विचार रखा गया है। पहले चरण में, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सूचना दी गयी कि उनके लेनदेन सर्वर से आंकड़ा प्रवाह उनके प्रबंध सूचना प्रणाली सर्वर में अबाध रूप से पहुंचना चाहिए जबकि

दूसरे चरण में बैंकों की प्रबंध सूचना प्रणाली से सभी विवरणियां जनरेट करने के कार्य में रिजर्व बैंक शामिल होगा। पहले चरण का कार्य प्रगति पर है और इसकी निगरानी और समीक्षा तत्पश्चात् अंतराल पर की जाती है। यह परियोजना मार्च 2013 तक पूरी होने की संभावना है। दूसरे चरण में, बैंकों के प्रबंध सूचना प्रणाली सर्वर से आंकड़ा प्रवाह सीधी प्रक्रिया से प्रवाहित होने के लिए रिजर्व बैंक एक प्रणाली शुरू करेगा।

4.65 आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से होने वाले लेनदेनों की मात्रा में हुई व्यापक वृद्धि को देखते हुए, आरटीजीएस प्रणाली की समीक्षा के लिए एक तकनीकी परामर्शदाता समूह बनाया गया था जिसमें प्रौद्योगिकी संस्थानों, बैंकों और रिजर्व बैंक से सदस्य लिए गए थे। इस समूह ने न्यू जनरेशन आरटीजीएस (एनजी-आरटीजीएस) प्रणाली बनाने की सिफारिश की जिसमें निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होंगी: (i) चलनिधि-बचत प्रणाली (ii) उन्नत क्यू प्रबंधन प्रणाली (iii) बैंक के आकार के अनुसार पहुंच के विभिन्न माध्यम (iv) एक्स्टेंसिबल मार्क-अप लैंग्वेज आधारित सूचना प्रणाली और (v) तत्काल समय की और लेनदेन निगरानी तथा नियंत्रण प्रणाली जिसमें डैशबोर्ड सुविधा भी होगी।

**10. ग्राहक सेवा**

4.66 कार्यकुशल और सुचारु रूप से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना भी रिजर्व बैंक की एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता रहा है। विभिन्न बैंकों और साथ ही रिजर्व बैंक में शिकायत निपटान प्रणाली की निगरानी करने और बैंकिंग लोकपाल योजना

**सारणी IV.31: बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों को प्राप्त क्षेत्रवार शिकायतें**

बीओ कार्यालय	शिकायतों की संख्या		प्रतिशत घटबढ़
	2010-11	2011-12	
अहमदाबाद	5,190	4,590	-11.6
बंगलूरु	3,470	3,486	0.5
भोपाल	5,210	5,953	14.3
भुवनेश्वर	1,124	1,826	62.5
चंडीगढ़	3,559	3,521	-1.1
चेन्नै	7,668	6,614	-13.7
गुवाहाटी	584	708	21.2
हैदराबाद	5,012	5,167	3.1
जयपुर	3,512	4,209	19.8
कानपुर	8,319	9,633	15.8
कोलकाता	5,192	4,838	-6.8
मुंबई	7,566	7,905	4.5
नई दिल्ली	10,508	9,180	-12.6
पटना	2,283	2,718	19.1
तिरुअनंतपुरम	2,077	2,541	22.3
<b>कुल</b>	<b>71,274</b>	<b>72,889</b>	<b>2.3</b>

स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय ।

कार्यान्वित करने के लिए जुलाई 2006 में रिजर्व बैंक में अलग ग्राहक सेवा विभाग बनाया गया। वर्तमान में, बैंकिंग लोकपाल देश के 15 प्रमुख बैंकिंग केंद्रों में कार्यरत हैं।

**कुल शिकायतों में से लगभग 40 प्रतिशत शिकायतें बड़े महानगरों में थीं**

4.67 देश में प्राप्त कुल शिकायतों में से लगभग 40 प्रतिशत शिकायतें बड़े महानगरों अर्थात नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै में प्राप्त हुई थीं (सारणी IV.31)।

**अधिकतर शिकायतें क्रेडिट/डेबिट कार्डों और उचित प्रथा संहिता के उल्लंघन से संबंधित थीं**

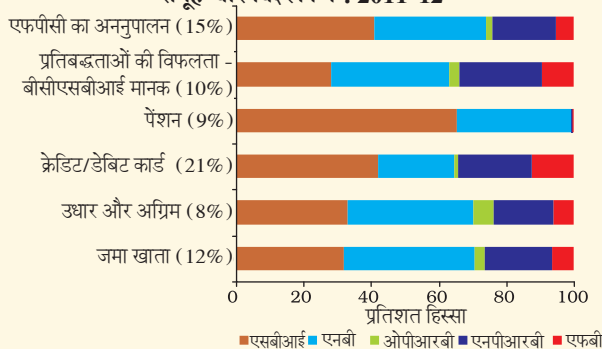
4.68 सभी 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों के श्रेणीवार आंकड़ों के अनुसार अधिकतर शिकायतें क्रेडिट/डेबिट कार्डों से संबंधित थीं जिनके बाद उचित प्रथा संहिता के उल्लंघन, जमाराशि खाते, बीसीएसबीआई कोड के तहत की गयी प्रतिबद्धताओं में विफलता और पेंशन संबंधी शिकायतों का स्थान था।

**कुल शिकायतों में लगभग दो-तिहाई शिकायतें सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित थीं**

4.69 पिछले वर्ष की प्रवृत्ति जैसे ही 2011-12 में भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध सर्वाधिक (70 प्रतिशत) शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत, 2011-12 के दौरान सर्वाधिक शिकायतें (लगभग 38 प्रतिशत) अकेले स्टेट बैंक समूह के बैंकों के विरुद्ध प्राप्त हुई थीं। यद्यपि सभी प्रकार की शिकायतों में स्टेट बैंक समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध 50 प्रतिशत से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं, किंतु इनमें पेंशन संबंधी शिकायतें अधिक थीं (चार्ट IV.24 और परिशिष्ट सारणी IV.7)।

4.70 इसके अलावा, बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में और विशेष रूप से जमा खाता, ऋण और अग्रिम, बीसीएसबीआई कोड के तहत

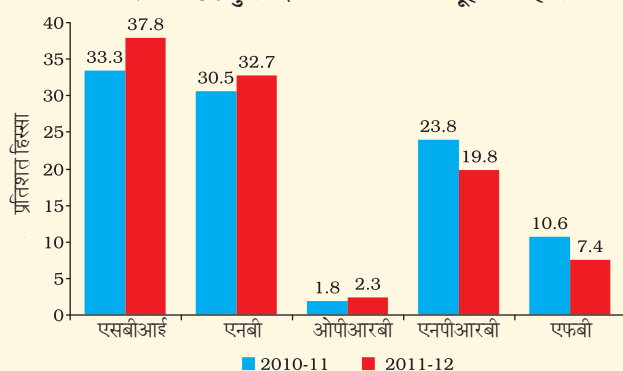
**चार्ट IV.24 क: प्रमुख शिकायतों का बैंक समूह-वार विश्लेषण : 2011-12**



एफपीसी: फेयर प्रैक्टिसेस कोड।

टिप्पणी: चार्ट IV.24क के कोष्टकों के आंकड़े 2011-12 के दौरान दर्ज कुल शिकायतों में क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का हिस्सा है।

**चार्ट IV.24.ख: कुल शिकायतों में बैंक समूहों का हिस्सा**



की गयी प्रतिबद्धताओं में विफलता और पेंशन संबंधी मामलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने की आवश्यकता है। इसके अलावा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड संबंधी सेवाओं के संबंध में हाल के वर्षों में ग्राहकों से बार-बार शिकायतें प्राप्त हुई हैं, अतः इस संबंध में सभी बैंक समूहों में सुधार की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी विकास के साथ नेट और मोबाइल बैंकिंग के क्षेत्र में ग्राहक सेवा को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि इन प्रौद्योगिकियों में ग्राहकों का विश्वास बढ़ सके।

4.71 ग्राहक डेटा बेस में और सुधार लाने की आवश्यकता है जिससे बैंकों को अपने ग्राहकों के ठिकानों का पता लगाने में सुविधा होगी और साथ ही धोखाधड़ी/धन शोधन के मामले रोकने में भी सहायता मिलेगी। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में यूनीक ग्राहक पहचान कोड नामक एक नई पहल शुरू की है (कृपया अध्याय III का बाक्स III.1 देखें)।

### **ग्राहक सतर्कता में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि सामान्य ग्राहकों की सहभागिता वाली धोखाधड़ियों को रोका जा सके**

4.72 बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग से हाल के समय में इंटरनेट बैंकिंग में धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ऐसी धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करते हुए बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग को बढ़ावा देना रिजर्व बैंक के हाल के समय में प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य रहा है। अनधिकृत निधि अंतरण, डुप्लिकेट कार्ड का उपयोग करके एटीएम से धोखाधड़ीपूर्ण आहरण, निजी सूचना प्राप्त करने के लिए फिशिंग ई-मेल का प्रयोग संबंधी शिकायतों में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

4.73 इसके अतिरिक्त, मोबाइल/नेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के क्षेत्रों में होने वाली धोखाधड़ी की घटनाएं रोकने के लिए एक मजबूत प्रणाली तैयार करना भी जरूरी है। इसके साथ ही, विभिन्न बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों द्वारा ग्राहक शिक्षा और सतर्कता में सुधार लाने के लिए शुरू की गयी पहलों को बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें बैंकों और राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग जरूरी होगा।

## **11. वित्तीय समावेशन**

4.74 समावेशक वृद्धि के लक्ष्य के समरूप रिजर्व बैंक ने हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन को उच्च प्राथमिकता दी है। रिजर्व बैंक ने हाल के वर्षों में देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के प्रयास किए हैं। इसमें शाखा प्राधिकृत करने की नीति में किया गया उदारिकरण और वाणिज्य बैंकों को उनकी कुल शाखाओं के कम-से-कम 25 प्रतिशत शाखाएं देश में अब तक बैंक-रहित क्षेत्रों में खोलने के निर्देश देना शामिल है। इसके अलावा, देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में पक्की शाखाएं खोलने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, रिजर्व बैंक बैंकों को बैंक बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट्स / बिजनेस पैसिलिटेटर्स के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहन देता आया है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने लाभ के लिए कार्यरत संगठनों को बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट्स के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी के लीवरेज को भी रिजर्व बैंक ने हाल के वर्षों में प्रोत्साहन दिया है। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल का प्रयोग इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए इन सभी उपायों के बावजूद, भारत में वित्तीय समावेशन का विस्तार उन्नत और विकासशील देशों की तुलना में निरंतर महत्वपूर्ण बना हुआ है (सारणी IV.32)।

### **सारणी IV.32: वित्तीय समावेशन के चयनित संकेतक-विभिन्न देशों की तुलना**

देश	शाखाओं की संख्या (प्रति 0.1 मिलियन वयस्क)	एटीएम की संख्या (प्रति 0.1 मिलियन वयस्क)	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बैंक उधार	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बैंक जमाराशियां
1	2	3	4	5
<b>भारत</b>	<b>10.64</b>	<b>8.90</b>	<b>51.75</b>	<b>68.43</b>
ऑस्ट्रेलिया	29.61	166.92	128.75	107.10
ब्राजील	46.15	119.63	40.28	53.26
फ्रान्स	41.58	109.80	42.85	34.77
मेक्सिको	14.86	45.77	18.81	22.65
यूनाइटेड स्टेट्स	35.43	-	46.83	57.78
कोरिया	18.80	-	90.65	80.82
फिलिपीन्स	8.07	17.70	21.39	41.93

टिप्पणी : - : आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सभी आंकड़े 2011 से संबंधित हैं।

स्रोत: वित्तीय एक्सेस सर्वेक्षण, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

## नई बैंक शाखाओं में से अधिकतर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोली गईं

4.75 नई बैंक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रयासों के अनुसरण में 2011-12 के दौरान खोली गईं नई शाखाओं में से आधे से अधिक शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोली गई थीं। क्षेत्रवार, खोली गईं नई शाखाओं में से लगभग 30 प्रतिशत दक्षिणी क्षेत्र में खोली गईं (सारणी IV.33)।

### बहुसंख्य नई बैंक शाखाएं टियर 2-6 में स्थित थीं

4.76 शाखा प्राधिकृत करने की नीति को उदार बनाने के परिणामस्वरूप बैंकों को टियर 2 से टियर 6 वाले केंद्रों में शाखा खोलने के लिए रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। 2011-12 में खोली गईं शाखाओं में से लगभग 70 प्रतिशत (4,831 बैंक शाखाएं) टियर 2 से टियर 6 वाले केंद्रों में खोली गईं।

### पक्की शाखाओं के स्थानापन्न के रूप में ऑफ साइट एटीएम

4.77 ऑफ साइट एटीएम स्वयंपूर्ण पक्की शाखा के बिना भी नकदी आहरण, निधि अंतरण जैसी आधारभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2011-12 में देश में 14,365 नए ऑफ साइट एटीएम जुड़े। किंतु नए एटीएम में से अधिकतर महानगरीय क्षेत्रों में खोले गए थे। नए एटीएम में से

सारणी IV.33 : 2011-12 के दौरान क्षेत्रवार और जनसंख्या समूहवार खोली गईं नई बैंक शाखाएं

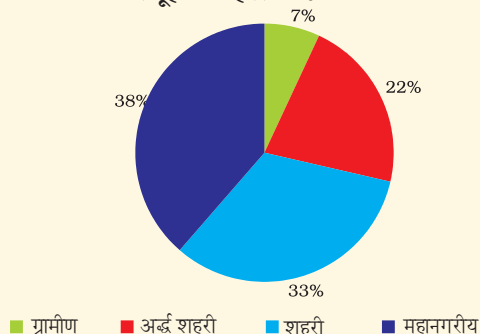
क्षेत्र	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
केंद्रीय	543	483	240	119	1,385
पूर्वी	301	352	217	89	959
पूर्वोत्तर	43	60	49	-	152
उत्तरी	450	425	187	205	1,267
दक्षिणी	647	871	315	247	2,080
पश्चिमी	269	387	122	297	1,075
<b>कुल</b>	<b>2,253</b>	<b>2,578</b>	<b>1,130</b>	<b>957</b>	<b>6,918</b>

अधिकतर दक्षिणी क्षेत्रों में खोले गए थे जिनके बाद उत्तरी क्षेत्र का स्थान था। किंतु, कुल एटीएम में ग्रामीण क्षेत्रों के एटीएम की संख्या कम ही बनी रही (चार्ट IV.25 और सारणी IV.34)।

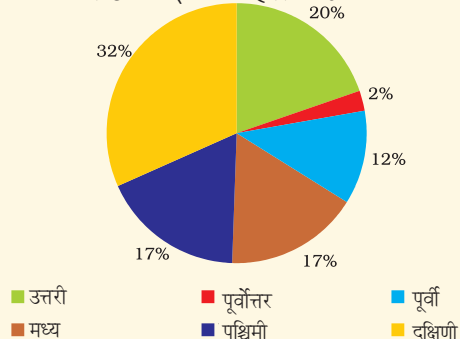
### 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी होने के करीब है

4.78 मार्च 2012 के अंत में, पहचाने गए 99 प्रतिशत गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराए गए। खोले गए नए बैंकिंग आउटलेटों में से 50 प्रतिशत से अधिक चार राज्यों, नामतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में हैं। एक सकारात्मक बात यह है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पहचान किए गए सभी गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराए गए हैं। बैंकिंग के विस्तार में हुई प्रगति के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चलता है

चार्ट IV.25क: एटीएम की वृद्धि में जनसंख्या समूहों का हिस्सा 2011-12



चार्ट IV.25ख: नए खोले गये कुल एटीएमों की संख्या में क्षेत्रों का हिस्सा 2011-12





**सारणी IV.34 : विभिन्न केंद्रों में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या**  
( मार्च 2012 के अंत में )

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
<b>सरकारी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>6,673</b>	<b>15,135</b>	<b>19,213</b>	<b>17,172</b>	<b>58,193</b>
	(11.5)	(26.0)	(33.0)	(29.5)	(100.0)
राष्ट्रीयकृत बैंक	3,383	6,800	10,186	10,681	31,050
	(10.9)	(21.9)	(32.8)	(34.4)	(100.0)
भारतीय स्टेट बैंक समूह	3,290	8,335	9,027	6,491	27,143
	(12.1)	(30.7)	(33.3)	(23.9)	(100.0)
<b>निजी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>1,937</b>	<b>7,520</b>	<b>11,525</b>	<b>15,097</b>	<b>36,079</b>
	(5.4)	(20.8)	(31.9)	(41.8)	(100.0)
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	523	2,025	1,876	1,347	5,771
	(9.1)	(35.1)	(32.5)	(23.3)	(100.0)
निजी क्षेत्र के नए बैंक	1,414	5,495	9,649	13,750	30,308
	(4.7)	(18.1)	(31.8)	(45.4)	(100.0)
<b>विदेशी बैंक</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>268</b>	<b>1,095</b>	<b>1,414</b>
	(2.1)	(1.6)	(19.0)	(77.4)	(100.0)
<b>कुल</b>	<b>8,639</b>	<b>22,677</b>	<b>31,006</b>	<b>33,364</b>	<b>95,686</b>
	(9.0)	(23.7)	(32.4)	(34.9)	(100.0)
<b>पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि</b>	<b>(20.7)</b>	<b>(25.4)</b>	<b>(28.9)</b>	<b>(32.4)</b>	<b>(28.4)</b>
<b>टिप्पणी :</b> कोष्ठक के आंकड़े प्रत्येक बैंक समूह के तहत कुल एटीएम के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं ।					

कि इस संबंध में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है (सारणी IV.35)।

**वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में सरकारी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं**

4.79 पहचान किए गए गांवों में नए बैंकिंग नेटवर्क के बैंक समूह-वार विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने प्रमुख भूमिका निभायी है (चार्ट IV.26)।

**सारणी IV.35: 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की प्रगति**  
(31 मार्च 2012 की स्थिति)

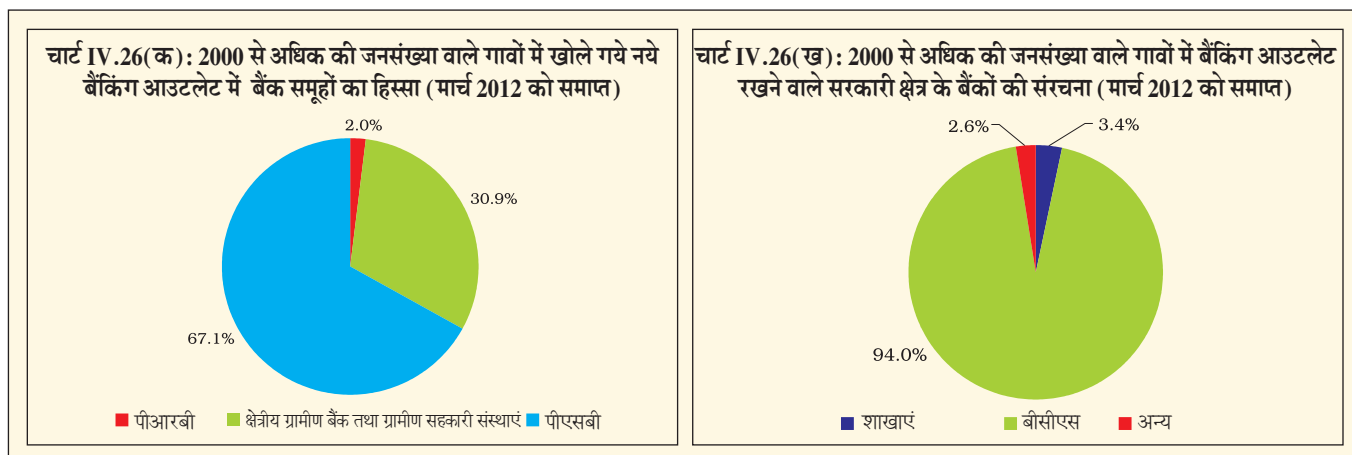
क्षेत्र	कवर किये गये गांवों की संख्या (मार्च 2010 तक)	2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में अप्रैल 2010 से मार्च 2012 के बीच खोले गये बैंकिंग आउटलेट			कुल	कवर किये गये कुल गांवों की संख्या (मार्च 2012 तक)	मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार मार्च 2012 में गांवों में बैंकिंग का प्रवेश
		शाखाएं	बीसी	अन्य साधन			
उत्तरी	4,363	241	7,868	67	8,176	12,539	2.9
पूर्वोत्तर	1,093	382	2,795	7	3,184	4,277	3.9
पूर्वी	6,767	444	19,019	579	20,042	26,809	4.0
केंद्रीय	6,935	491	19,256	535	20,282	27,217	3.9
पश्चिमी	3,409	208	6,849	816	7,873	11,282	3.3
दक्षिणी	5,894	727	13,587	328	14,642	20,536	3.5
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>28,461</b>	<b>2,493</b>	<b>69,374</b>	<b>2,332</b>	<b>74,199</b>	<b>1,02,660</b>	<b>3.6</b>

4.80 इसके अलावा, सभी लाभों को सीधे ही लाभार्थी के खाते में अंतरित करने के सरकारी आदेश के अनुसरण में रिजर्व बैंक बैंकों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वे इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण व्यवस्था लागू करें। हो सकता है कि सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थी 2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में रहते हों, अतः छोटे गांवों में इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण-समर्थित बैंक खाते तत्काल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

**इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण प्रणाली लागू करने के लिए किए गए प्रयास**

4.81 रिजर्व बैंक ने जून 2012 में राज्य स्तरीय बैंक समिति की बैठकों का आयोजन करने वाले बैंकों को सूचित किया कि 2000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गांवों को कवर करते हुए योजना बनाएं और समयबद्ध तरीके से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को इन गांवों का आबंटन करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ में देश में प्रत्येक गांव में बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट्स पॉइंट होना चाहिए।

4.82 इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया कि प्रारंभ में वे आबंटित गांवों में बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट्स के नियमित संपर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण के लाभार्थियों को डोर स्टेप सेवाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दें ताकि यह एक स्वयं सक्षम कारोबारी मॉडल बन सके; और कुछ समय बाद यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं, नामतः प्रेषण, आवर्ती जमा, केसीसी और जीसीसी के माध्यम से उद्यमी ऋण, और अन्य बैंकिंग सेवाएं गांव के सभी निवासियों के लिए



पक्की शाखाओं और कारोबार संपर्की नेटवर्क के संयुक्त रूप में उपलब्ध हो जाएं।

4.83 तत्कालीन 'एक जिला एक बैंक' मॉडल के तहत संबंधित जिले के सभी गांवों में इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण लागू करने में एक शीर्ष बैंक को आयी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 'इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण लागू करने संबंधी अपने परिचालनात्मक दिशानिर्देश और वित्तीय समावेशन के साथ इसका समन्वय' में 'एक जिला-अनेक बैंक-एक नेता बैंक' मॉडल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण लागू करने की सिफारिश की। इस मॉडल के तहत, संबंधित जिले में उपस्थित सभी बैंक इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण में सहभागी होंगे हालांकि प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार नेता बैंक के साथ ही संपर्क करेगी। यह संशोधित मॉडल सरल और स्तरबद्ध होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण लागू करने के कार्य में गति आने की संभावना है।

### वित्तीय समावेशन योजना प्रगति पर है

4.84 सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अप्रैल 2010 से अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना शुरू करें। वित्तीय समावेशन योजना में सामान्यतः निम्नलिखित के संबंध में स्व-निर्धारित लक्ष्य शामिल होने चाहिए: i) ग्रामीण पक्की शाखाएं खोलना; बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट्स को नियोजित करना; ii) शाखाओं/बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट्स /अन्य मॉडलों के माध्यम से 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों और साथ ही 2000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गांवों को कवर करना; iii) बीसी-

आईसीटी के माध्यम से शामिल करते हुए नो-फ्रिल खाते खोलना; iv) वित्तीय दृष्टि से अलग रह गए लोगों के लिए उनके द्वारा विशेष रूप से बनाए गए उत्पाद और किसान क्रेडिट कार्ड तथा जनरल क्रेडिट कार्ड जारी करना।

4.85 बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन योजना लागू करने में पिछले दो वर्षों में की गयी प्रगति सराहनीय रही है। इस प्रगति के संक्षिप्त विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का काफी अच्छा विस्तार हुआ है। मार्च 2012 के अंत में, कारोबार संपर्की के माध्यम से कवर किए गए गांव वित्तीय समावेशन योजना के तहत कवर हुए कुल गांवों के 80 प्रतिशत से अधिक थे। इससे पता चलता है कि ग्रामीण भारत में बैंकों और ग्राहकों द्वारा वित्तीय समावेशन योजना के बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट्स मॉडल को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

### आईसीटी-आधारित खातों के माध्यम से हुए लेनदेन की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई

4.86 नो-फ्रिल्स खातों से छोटे ग्राहक इन-बिल्ट ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में व्यवस्थित रूप से ऋण प्राप्त कर पाते हैं। मार्च 2012 के अंत में नो-फ्रिल्स खातों की संख्या 100 मिलियन से आगे निकल गयी थी। किंतु इन नो-फ्रिल्स खातों में से मात्र दो प्रतिशत में ही ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध थी। इस संबंध में एक अच्छी बात यह देखी गयी है कि नो-फ्रिल्स खातों के प्रतिशत के रूप में आईसीटी-आधारित खातों की संख्या में पिछले दो वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है जो ग्रामीण ग्राहकों के बीच आईसीटी-आधारित उत्पादों की स्वीकार्यता में वृद्धि दर्शाती है।

4.87 आगामी वर्षों में नो-फ्रिल्स खातों में हुए लेनदेनों की संख्या और मूल्य तथा आईसीटी-आधारित बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट्स आउटलेटों के माध्यम से वितरित ऋण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके मुख्यालयों द्वारा तैयार की गयी वित्तीय समावेशन योजनाएं संबंधित नियंत्रक कार्यालयों और शाखा स्तर पर वितरित की जाती हैं और इन स्तरों पर होने वाली प्रगति की आवधिक निगरानी की प्रणाली लागू की जाती है। बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन योजना के तहत की गयी प्रगति का ब्योरा सारणी IV.36 में दिया गया है।

### एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम और माइक्रो फाइनेंस

4.88 स्व-सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत नाबार्ड ने 1992 में प्रायोगिक तौर पर की थी जिसमें तीन एजेंसियां, नामतः स्व-सहायता समूह, बैंक और गैर-सरकारी संगठन शामिल थे। शुरुआत में स्व-सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की प्रगति धीमी थी, किंतु 1999 से इसका तेजी से विस्तार हुआ। मार्च 2012 के अंत में, 103 मिलियन ग्रामीण हाउसहोल्डों की विभिन्न बैंकों से जुड़े 7.96 मिलियन स्व-

सहायता समूहों के माध्यम से नियमित बचत तक पहुंच थी। बैंकों में बचत खाता बनाए रखने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या में 2011-12 के दौरान वृद्धि हुई, किंतु पिछले वर्ष की तुलना में बैंकों में स्व-सहायता समूहों की बचत की शेष राशि में गिरावट आयी है।

4.89 हाल के वर्षों में माइक्रो-फाइनेंस संस्थाएं देश के ग्रामीण भागों में ऋण चैनलिंग के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी हैं जिसका कारण इन क्षेत्रों में उनकी व्यापक पहुंच और औसत ग्रामीण ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत करने की उनकी योग्यता है (सारणी IV.37)।

## 12. स्थानीय क्षेत्र के बैंक

4.90 स्थानीय क्षेत्र के बैंक वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय क्षेत्र के बैंक 1996 में अस्तित्व में आए जो कि 500 मिलियन ₹ की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी के साथ निजी क्षेत्र में स्थानीय बैंकों की स्थापना के रिजर्व बैंक के प्रयासों का नतीजा थे। यह अपेक्षा की गई थी कि स्थानीय क्षेत्र

### सारणी IV.36: वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4
1	नियोजित किए गए कुल ग्राहक सेवा पॉइंट की संख्या	60,993	1,16,548
2	गावों में कुल बैंकिंग आउटलेट, जिसमें से	1,16,208	1,81,753
	2.1 शाखाएं	34,811	37,471
	2.2 बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट	80,802	1,41,136
	2.3 अन्य माध्यम	595	3146
3	बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	3,771	5,891
4	बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित खाते (संख्या मिलियन में)	32	57
5	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित खाते-लेनदेन (संख्या मिलियन में)	84	141
6	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित खाते लेनदेन (राशि बिलियन में)	58	93
7	नो फ्रिल खातों की संख्या (मिलियन में)	105	139
8	नो फ्रिल खातों में राशि (₹ बिलियन में)	76	120
9	ओडी सहित नो फ्रिल खातों की संख्या (मिलियन में)	0.6	2.7
10	ओडी सहित नो फ्रिल खातों में राशि (₹ बिलियन में)	0.3	1.1
11	बकाया केसीसी की संख्या (मिलियन में)	27	30
12	बकाया केसीसी की राशि (₹ बिलियन में)	1,600	2,068
13	बकाया जीसीसी की संख्या (मिलियन में)	1.7	2.1
14	बकाया जीसीसी की राशि (₹ बिलियन में)	35	42

### सारणी IV.37: माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रमों की प्रगति (मार्च की समाप्ति पर)

मद	स्वयं सहायता समूह*					
	संख्या (मिलियन में)			राशि (₹ बिलियन में)		
	2009-10	2010-11	2011-12अ	2009-10	2010-11	2011-12अ
बैंकों द्वारा संवितरित उधार	1.5 (0.27)	1.2 (0.2)	1.1 (0.2)	145 (22)	145 (25)	165 (26)
बैंकों के पास बकाया उधार	4.8 (1.3)	4.8 (1.3)	4.4 (1.2)	280 (63)	312 (78)	363 (80.5)
बैंकों के पास बचतें	6.9 (1.7)	7.5 (2.0)	8.0 (2.1)	62 (13)	70 (18)	66 (14)
मद	माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं					
	संख्या (मिलियन में)			राशि (₹ बिलियन में)		
	2009-10	2010-11	2011-12अ	2009-10	2010-11	2011-12अ
बैंकों द्वारा संवितरित उधार	691	469	465	81	76	52
बैंकों के पास बकाया उधार	1,513	2,176	1,960	101	107	115

**टिप्पणी:** 1. \* कोष्ठकों के आंकड़े स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत आनेवाले स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) संबंधी ब्योरा दर्शाते हैं।  
2. अ: अंतिम आंकड़े।  
**स्रोत:** नाबार्ड।

**सारणी IV.38: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का प्रोफाइल**  
( मार्च के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

बैंक	आस्तियां		जमा		सकल अग्रिम	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	7.50 (67.8)	9.67 (71.0)	6.48 (72.3)	8.20 (73.8)	4.20 (65.2)	5.18 (67.2)
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	1.58 (14.3)	1.93 (14.2)	1.22 (13.6)	1.51 (13.6)	1.00 (15.6)	1.26 (16.4)
कृष्ण भीम समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	1.38 (12.4)	1.35 (9.9)	0.93 (10.3)	1.00 (9.0)	0.88 (13.7)	0.84 (10.9)
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	0.61 (5.5)	0.68 (5.0)	0.34 (3.8)	0.39 (3.5)	0.36 (5.5)	0.43 (5.6)
<b>स्थानीय क्षेत्र के सभी बैंक</b>	<b>11.07</b> <b>(100)</b>	<b>13.63</b> <b>(100)</b>	<b>8.97</b> <b>(100)</b>	<b>11.10</b> <b>(100)</b>	<b>6.44</b> <b>(100)</b>	<b>7.71</b> <b>(100)</b>

**टिप्पणी :** कोष्ठकों के आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं। आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

**स्रोत :** ऑफ साइट विवरणियों (घरेलू) पर आधारित।

के बैंक कृषि और संबंधित कार्यों, लघु उद्योगों, कृषि-औद्योगिक कार्यों, व्यापार कार्यों और कृषीतर क्षेत्रों को ऋण देंगे। स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को एएनबीसी के 40 प्रतिशत का प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य और इसमें से न्यूनतम 25 प्रतिशत कमजोर वर्गों को देने का लक्ष्य पूरा करना होता है।

4.91 रिजर्व बैंक ने शुरू में छह स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस दिया था किंतु बाद के वर्षों में उनमें से चार ही कार्यरत रह पाए। इन चार बैंकों में से अकेले कैपिटल लोकल एरिया बैंक की आस्तियां सभी चार स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की कुल आस्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक थीं (सारणी IV.38 और IV.39)।

**सारणी IV.39 : स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय निष्पादन**

(राशि ₹ बिलियन में)

1	राशि		प्रतिशत घटबढ़	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
<b>1. आय (i+ii)</b>	<b>1.2</b>	<b>1.5</b>	<b>19.2</b>	<b>25.0</b>
i) ब्याज आय	1.1	1.4	24.4	27.3
ii) अन्य आय	0.2	0.2	-5.6	-
<b>2. खर्च (i+ii+iii)</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>	<b>15.4</b>	<b>18.2</b>
i) व्यय किया गया ब्याज	0.6	0.8	7.8	33.3
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.1	0.1	62.5	7.7
iii) परिचालन व्यय	0.4	0.4	15.6	-
जिसमें से: वेतन बिल	0.2	0.2	21.4	-
<b>3. लाभ</b>				
i) परिचालन लाभ / हानि	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>52.4</b>	-
ii) निवल लाभ / हानि	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>46.2</b>	-
<b>4. अंतर (निवल ब्याज आय)</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>48.6</b>	<b>20.0</b>
<b>5. कुल आस्तियां</b>	<b>11.1</b>	<b>13.6</b>	<b>17.0</b>	<b>22.5</b>
<b>6. वित्तीय अनुपात @</b>				
i) परिचालन लाभ	3.0	2.6	-	-
ii) निवल लाभ	1.8	1.5	-	-
iii) आय	12.1	12.3	-	-
iv) ब्याज आय	10.5	11.0	-	-
v) अन्य आय	1.6	1.3	-	-
vi) व्यय	10.3	10.8	-	-
vii) व्यय किया गया ब्याज	5.4	6.2	-	-
viii) परिचालन व्यय	3.7	3.6	-	-
ix) वेतन बिल	1.6	1.7	-	-
x) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1.2	1.1	-	-
xi) स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	5.1	4.9	-	-

**टिप्पणी** 1. @कुल औसत आस्तियों का अनुपात।  
2. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।  
3. - : कुछ नहीं/ नगण्य।

**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियों पर आधारित।

### 13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4.92 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों जैसे ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकित तुलनपत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि हुई। देयता पक्ष में, कम वृद्धि का मुख्य कारण जमाराशि और उधार में कम वृद्धि था। आस्ति पक्ष में, तुलनपत्र में गिरावट का कारण रिजर्व बैंक में रखे शेषों में कमी आना और निवेश में गिरावट होना था। यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशि में चालू खाता और बचत खाता जमाराशि का हिस्सा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऐसे हिस्से की तुलना में अधिक था (सारणी IV.40)।

4.93 2011-12 के दौरान, देश में कार्यरत कुल 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 75 लाभ की स्थिति में जबकि शेष सात हानि की स्थिति में थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवल लाभ में हाल के

#### सारणी IV.40: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

क्रम सं.	मद सं.	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
		2011	2012अ	2010-11	2011-12अ
1	शेयर पूंजी	2	2	0.0	0.0
2	आरक्षित निधियां	96	113	18.6	17.9
3	शेयर पूंजी जमा	41	50	2.3	22.3
4	जमाराशियां	1,662	1,863	14.6	12.1
	4.1 चालू	92	104	13.9	12.7
	4.2 बचत	911	986	20.1	8.2
	4.3 सावधि	659	774	7.9	17.4
5	से लिए गए उधार	265	303	41.1	14.3
	5.1 नाबार्ड	160	213	28.2	33.0
	5.2 प्रायोजक बैंक	98	88	58.3	-10.4
	5.3 अन्य	7	2	696.4	-71.4
	5.4 अन्य देयताएं	88	95	9.5	7.4
	<b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>	<b>2,154</b>	<b>2,425</b>	<b>17.0</b>	<b>12.6</b>
6	नकदी	21	23	19.1	9.5
7	आरबीआई के पास शेष	99	89	20.9	-10.2
8	अन्य बैंक शेष	452	478	15.6	5.9
9	निवेश	542	603	14.5	11.2
10	ऋण और अग्रिम (निवल)	947	1,130	19.7	19.3
11	अचल आस्तियां	5	7	21.1	40.0
12	अन्य आस्तियां #	89	96	7.5	7.9

जापन मद

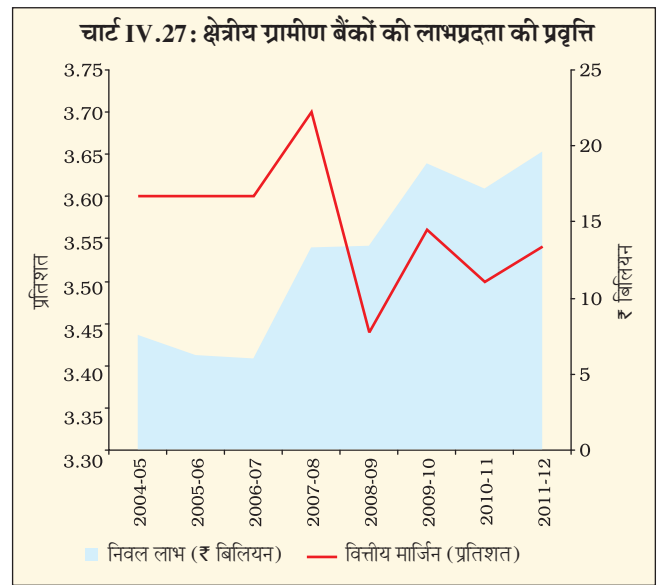
1	ऋण-जमा अनुपात	59.5	63.3
2	निवेश-जमा अनुपात	52.0	49.8
3	(ऋण + निवेश) - जमा अनुपात	111.5	113.1

टिप्पणी: 1. अ: अर्नातिम

2. # संचित हानि सहित।

3. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

स्रोत: नाबार्ड।



वर्षों में सुधार हुआ किंतु उनके निवल मार्जिन में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गयी (चार्ट IV.27 और सारणी IV.41)।

#### सारणी IV.41: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

क्रम सं.	मद सं.	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
		2011	2012अ	2010-11	2011-12अ
1	2	3	4	5	6
1	<b>आय (i + ii)</b>	<b>162</b>	<b>201</b>	<b>17.2</b>	<b>24.1</b>
	i ब्याज आय	152	189	17.6	24.3
	ii अन्य आय	10	11	12.4	10.0
2	<b>व्यय (i+ii+iii)</b>	<b>145</b>	<b>181</b>	<b>21.4</b>	<b>24.8</b>
	i ब्याज व्यय	86	112	16.7	30.2
	ii परिचालन व्यय	49	55	38.0	12.2
	जिसमें से: वेतन बिल	38	40	42.9	5.3
	iii प्रावधान और आकस्मिक व्यय	10	13	-3.9	30.0
3	<b>लाभ</b>				
	i परिचालन लाभ	27	33	-6.9	22.2
	ii निवल लाभ	17	20	-8.5	17.6
4	<b>कुल आस्तियां</b>	<b>2,154</b>	<b>2,425</b>	<b>17.0</b>	<b>12.6</b>
5	<b>वित्तीय अनुपात #</b>				
	i परिचालन लाभ	1.3	1.4		
	ii निवल लाभ	0.8	0.8		
	iii आय (क+ख)	7.5	8.3		
	(क) ब्याज आय	7.0	7.8		
	(ख) अन्य आय	0.5	0.5		
	iv व्यय (क+ख+ग)	6.7	7.4		
	(क) व्यय किया गया ब्याज	4.0	4.6		
	(ख) परिचालन व्यय	2.3	2.3		
	जिसमें से: वेतन बिल	0.6	1.6		
	(ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.5	0.5		

टिप्पणी: 1. अ: अर्नातिम

2. #: वित्तीय अनुपात औसत कुल आस्तियों के संबंध में है।

3. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

4. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण घटकों और उनके योग में अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

**सारणी IV.42: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण का प्रयोजन-वार वितरण**

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	प्रयोजन	मार्च को समाप्त	
		2011	2012अ
1	2	3	4
1.	कृषि (i से iii)	<b>551</b> (55.7)	<b>641</b> (53.2)
	i अल्पकालिक ऋण (फसल ऋण)	407	474
	ii मीयादी ऋण (कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए)	144	167
	iii अप्रत्यक्ष अग्रिम	-	-
2.	कृषि से इतर (i से iv)	<b>439</b> (44.3)	<b>564</b> (46.8)
	i ग्रामीण कारीगर	9	11
	ii अन्य उद्योग	26	36
	iii खुदरा व्यापार	51	66
	iv अन्य प्रयोजन	353	452
<b>कुल (1+2)</b>		<b>989</b>	<b>1,206</b>
<i>ज्ञापन मर्दे:</i>			
(क)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	826	974
(ख)	गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	163	231
(ग)	कुल ऋण में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा	83.5	80.8
<b>टिप्पणी:</b> 1. अ: अनंतिम - : कुछ नहीं/ नगण्य।			
2. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकते हैं।			
3. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।			
<b>स्रोत:</b> नाबार्ड।			

4.94 मार्च 2012 के अंत में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल ऋण में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 80 प्रतिशत से अधिक थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण की उद्देश्य-वार संरचना 2011-12 के दौरान अपरिवर्तित रही जिसमें से कुल में से आधे से अधिक ऋण कृषि क्षेत्र को दिये गये थे (सारणी IV.42)।

**समग्र आकलन**

4.95 2011-12 के दौरान बैंकों का निष्पादन देशी अर्थव्यवस्था में नरमी और उच्च ब्याज दर के वातावरण से प्रभावित था। किंतु भारतीय बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत रहे। इसके अलावा, कम लागत-आय अनुपात और निवल ब्याज मार्जिन के कारण बैंकों की कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। वित्तीय समावेशन योजना के तहत बैंकों द्वारा की गयी प्रगति सामान्यतः संतोषजनक थी।

**बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट चिंता का विषय बना हुआ है**

4.96 बैंकों के मामले में सामान्य रूप से और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में विशेष रूप से, अनर्जक आस्तियों में हुई तेज वृद्धि से आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आना गंभीर चिंता के रूप में उभरा है। इसके अलावा, स्लिपेज अनुपात से, अनर्जक आस्तियों में नए सिरे से भी काफी वृद्धि हुई है। साथ ही, प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में गिरावट आयी। बैंकों द्वारा अग्रिमों के पुनर्निर्धारण का व्यापक रूप से सहारा लेने के बावजूद, दीर्घावधि में आस्ति गुणवत्ता पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि इन पुनर्निर्धारित अग्रिमों के अशोध्य ऋण बनने की संभावना रहती है।

**आस्ति-देयता असंतुलन पर बुनियादी सुविधा उधार के प्रभाव की सूक्ष्म निगरानी आवश्यक है**

4.97 बैंकों की चलनिधि की स्थिति तनावग्रस्त रही जो 2011-12 के दौरान के नीतिगत वातावरण तथा संरचनात्मक मुद्दों को दर्शाती है। बुनियादी सुविधा ऋण वृद्धि मंद रहने के बावजूद यह उद्योग को प्राप्त कुल बैंक ऋण का लगभग एक-तिहाई बनी रही। निर्माण आरंभ से उत्पादन शुरू होने की दीर्घ अवधि वाली बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के प्रति व्यापक एक्सपोजर बैंकिंग क्षेत्र में पहले से ही मौजूद अवधिपूर्णाता संबंधी असंतुलन को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ते अशोध्य ऋण और बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के प्रति दीर्घकालिक एक्सपोजर की सावधानीपूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता है।

**प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य पूरा करने में बैंकों की असमर्थता चिंता का विषय बना हुआ है**

4.98 2011-12 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के अधिकतर बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य पूरा करने में विफल रहे। समग्र स्तर पर विदेशी बैंकों का निष्पादन देशी बैंकों की तुलना में बेहतर रहने के बावजूद, बैंकवार आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ विदेशी बैंक भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य पूरा करने में विफल रहे।

### **वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा में और सुधार की आवश्यकता है**

4.99 विभिन्न बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकतर शिकायतें सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित थीं। अतः ग्राहक सेवा और विशेष रूप से पेंशन खातों के संबंध में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि शिकायतों में पेंशन संबंधी शिकायतों का हिस्सा बहुत अधिक था। इसके अलावा, हाल के वर्षों में ग्राहकों की

शिकायतों पर बैंकों द्वारा उचित प्रथा संहिता के अननुपालन का परिणाम भी पड़ा। वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति संतोषजनक रहने के बावजूद, अब भी काफी लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि वित्तीय समावेशन के मामले में भारत अन्य कुछ प्रमुख विकासशील देशों से पिछड़ा हुआ है। बैंकिंग में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ने के साथ, नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के क्षेत्र में ग्राहक सेवा में और सुधार लाने पर अधिक बल देने और विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को और विकसित करने की आवश्यकता है।